

रायपुर, जबलपुर, कटनी, मंडला, भोपाल, इंदौर, मुंबई, दिल्ली, नरसिंहपुर, सितनी से एक साथ प्रकाशित

yashbharat.co.in

नये जमाने के साथ..

यशभारत

● वर्ष- 01 अंक-78 ● रायपुर ● बुधवार, 30 सितम्बर , 2026 ● मूल्य- 4 रुपए ● पृष्ठ-8 ● अभिन कृष्ण , पक्ष 4 ● विक्रम संवत् 2083

एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड की बारिश, रिकॉर्ड की झड़ी

4 गुणा400 में सोना, नीरू का ऐतिहासिक निशाना, गुलवीर की मेडल हैट्रिक

नागोया, जापान, एजेंसी। एशियन गेम्स 2026 में भारत ने मंगलवार को ट्रैक और शूटिंग रेंज पर शानदार प्रदर्शन किया। महिला 4×400 मीटर रिले में स्वर्ण जीतकर भारत ने छह गोल्ड पूरे किए। इससे पहले निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिलाओं की व्यक्तिगत ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा। गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर में कांस्य जीतकर एक ही एशियाड में तीन व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बनने की उपलब्धि हासिल की। पुरुष 4×400 मीटर और मिश्रित 4×100 मीटर रिले में भी भारत ने कांस्य पदक जीते।

महिला 4×400 मीटर रिले में किरण, मचेतिरा पूवमा, प्राची और विथ्या रामराज ने 3ः29.69 सेकेंड में रस पूरी की। बहरीन को रजत और चीन को कांस्य मिला। इस स्वर्ण के साथ भारत ने एशियन गेम्स में लगातार छठी बार 50 या उससे अधिक पदक हासिल करने का सिलसिला कायम रखा। 2006 के बाद से भारत हर एशियाड में 50



से ज्यादा पदक जीत चुका है।

शूटिंग में नीरू ढांडा ने 30 में से 28 निशाने सटीक लगाकर व्यक्तिगत ट्रैप में स्वर्ण जीता। चीन की यूनॉन सुन को रजत मिला। नीरू इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। 1990 में एशियन गेम्स में शामिल हुई इस स्पर्धा में भारत को 36 साल तक कोई पदक नहीं मिला था। नीरू ने इस लंबे इंतजार को

स्वर्ण पदक जीता। करीब 10 दिन पहले फ्लू के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनका यह प्रदर्शन खास रहा। इससे पहले वह टीम ट्रैप में रजत जीत चुकी हैं।गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर में 13ः32.75 सेकेंड के समय के साथ कांस्य जीता। बहरीन के बिरहानु बालेव ने स्वर्ण और जापान के तोमोनोरी यामागुची ने रजत हासिल किया। गुलवीर ने इससे पहले 10,000 और



खत्म करते हुए सीधे

1500 मीटर में रजत पदक जीते थे। इस तरह उनके खाते में तीन व्यक्तिगत पदक हो गए।पुरुष 4×400 मीटर रिले में भारत ने 3ः20.1.61 का सीजन बेस्ट समय निकालकर कांस्य जीता। जापान और कतर ने स्वर्ण और रजत हासिल किया। 4×100 मीटर मिश्रित रिले में भी भारत को कांस्य मिला। मंगलवार की उपलब्धियों ने भारतीय एथलेटिक्स और निशानेबाजी अभियान को खास बना दिया।

अरुणाचल में भारत-म्यांमार सीमा पर उग्रवादी हमला

असम राइफल्स का जवान शहीद

4 घायल; गश्त के दौरान फायरिंग

इटानगर, एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में मंगलवार को उग्रवादी हमले में असम राइफल्स का एक जवान शहीद हो गया। 4 अन्य जवान घायल हो गए। हमला भारत-म्यांमार सीमा के पास नामपोंग सर्कल में सुबह करीब 6.30 बजे हुआ। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार हमला नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का (युंग आंग गुट) के उग्रवादियों ने किया है। गश्त के दौरान गोलीबारी में हवलदार जानखोकाई कुकी (42) शहीद हो गए। हमला नामपोंग नाले के पास हुआ। इस इलाके में सीमा पर बाड़ लगाने का काम चल रहा है। शुरुआती जांच और खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि घात लगाकर किए गए हमले के लिए (नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का युंग आंग गुट) के उग्रवादी जिम्मेदार हैं। हमले के बाद, भारतीय सेना और जिला पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की और भाग रहे उग्रवादियों को पकड़ने के लिए आस-पास के जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। पूर्वोत्तर सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा एजेंसियों को हार्ड अलर्ट पर रखा गया है।अधिकारी ने कहा कि घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सच अभियान तेज कर दिया है।चांगलांग के एसपी किल्ली पाडु ने कहा कि उन्हें घटना के बारे में जानकारी मिली है और उन्होंने चांगलांग पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को विवरण इकट्ठा करने का निर्देश दिया है।

हमला NSCN-K-YA गुट ने किया

शुरुआती जांच और खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि घात लगाकर किए गए हमले के लिए NSCN-K-YA (नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का युंग आंग गुट) के उग्रवादी जिम्मेदार हैं।हमले के बाद, भारतीय सेना और जिला पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की और भाग रहे उग्रवादियों को पकड़ने के लिए आस-पास के जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया।

कैंसर दवा 2700 की, एमआरपी 27 हजार कैसे?

सुको ने कहा- यह नरसंहार जैसा

नई दिल्ली, एजेंसी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के इलाज में दवाओं की आसमान छूती कीमतों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सदीप मेहता की पीठ ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि जिस कैंसर की दवा की कीमत करीब 2700 रुपए है, उस पर 27 हजार रुपए की कीमत कैसे लिखी जा सकती है। सुनुवाई के दौरान कोर्ट ने दवाओं की कीमतों में इस तरह के अंतर को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए इसे “नरसंहार” जैसा बताया।दवाओं की कीमत और जेनैरिक दवाओं से संबंधित याचिकाओं पर सुनुवाई के दौरान अदालत ने यह भी पूछा कि सरकारी योजनाओं के तहत इलाज करा रहे मरीजों को जब महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं तो इस अतिरिक्त खर्च का भार आखिर कौन उठाता है। कोर्ट ने कहा कि अंततः इसका बोझ सरकारी खजाने और टैक्सपेयर्स पर पड़ता है।

अदालत ने निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कई अस्पताल मरीजों को अपनी ही फार्मसी से दवा खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। सुनुवाई के दौरान सॉलिडिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि फार्मा कंपनियां लाभ कमाने वाली नहीं हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि मुनाफा कमाने वाले निजी अस्पताल हैं। इसके जवाब में याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि जिन दवाओं की कीमत सरकार नियंत्रित करती है, उनका बाजार में हिस्सा सीमित है, जबकि जिन दवाओं की कीमत सरकार तय नहीं करती, उनकी हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कीमतों के इस अंतर का सीधा असर मरीजों के इलाज के कुल खर्च पर पड़ता है।

विजयवाड़ा में महिला की हत्या, शव के टुकड़े नहर में फेंके

विजयवाड़ा, एजेंसी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक महिला की हत्या के बाद शव के टुकड़े कर नहर में फेंकने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, पैसों को लेकर हुए विवाद में एक कसाई ने अपनी परिचित महिला की कथित तौर पर हत्या कर दी। इसके बाद शव को कई हिस्सों में काटकर नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने मामले में दो संदिग्धों से पूछताछ शुरू की है। मृतका की पहचान कल्याणी के रूप में हुई है। पुलिस को इब्राहिमपट्टनम इलाके में एक अज्ञात महिला का शव मिला था।

सोशल मीडिया पर शव की जानकारी सामने आने के बाद परिजनों ने उसके हाथ पर बने टैटू के आधार पर पहचान की। इसके बाद पुलिस ने हत्या की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस का शक भवानीपुरम में मटन की दुकान चलाने वाले शफी पर गया। पुलिस के अनुसार, शफी और कल्याणी एक-दूसरे को जानते थे और दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था।

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल, 125 अफसरों का तबादला

रायपुर, यशभारत। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 125 अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को तबादला आदेश जारी कर अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। फेरबदल में अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और प्रवर श्रेणी के अधिकारी शामिल हैं। जिलों से लेकर मंत्रालय और विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारियों के दायित्व बदले गए हैं। तबादला आदेश में कई अधिकारियों को वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ अतिरिक्त प्रभार सौंप गए हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। पुलक भट्टाचार्य को राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा), रायपुर के

अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भट्टाचार्य सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव के साथ पीएमओटी मिशन कर्मयोगी के समन्वयक तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय में अपर संचालक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। अब इन जिम्मेदारियों के साथ सूडा का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास रहेगा।

विपुल कुमार गुप्ता को भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। श्रम विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ गुप्ता को वर्तमान दायित्वों के साथ छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, रायपुर के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।विनायक शर्मा को नवा रायपुर अटल



नगर विकास प्राधिकरण में प्रबंधक बनाया गया है। शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षाचार कार्यालय में राज्य शिक्षाचार अधिकारी के पद पर पदस्थ थे और उनके पास उप सचिव, खनिज साधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी था। आदेश के तहत उन्हें

नई पदस्थापना दी गई है।डॉ. ऋतु वर्मा को वर्तमान दायित्वों के साथ उच्च शिक्षा विभाग में उप सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वे सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव (कक्ष-6 एवं 7) के पद पर पदस्थ हैं।

वहीं, वैभव कुमार क्षेत्रज्ञ को छत्तीसगढ़ संवाद के उप महाप्रबंधक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। वे कृषि विकास, किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग में अवर सचिव के पद पर पदस्थ हैं। उनके अन्य दायित्व यथावत रखे गए हैं।

पुणेन्द्र कुमार शर्मा को राज्य शिक्षाचार अधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के पद पर पदस्थ किया गया है। वे इससे पहले राज्य शिक्षाचार

अधिकारी कार्यालय में सत्कार अधिकारी के पद पर कार्यरत थे।इसी तरह सुशासन-अभिसरण विभाग में अवर सचिव गौतम सिंह को मार्केट के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। उनके शेष दायित्व यथावत रहेंगे।माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर में उप सचिव के पद पर पदस्थ मोनिका जयनशोने को डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया गया है। वे नवाचार आयोग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रही थीं। आदेश के बाद उनकी नई जिम्मेदारी जिला प्रशासन से जुड़ गई है।सरकार के इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल से विभिन्न जिलों और विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है। आदेश में शामिल 125 अधिकारियों की पूरी सूची में अलग-अलग जिलों और विभागों में पदस्थापना एवं अतिरिक्त प्रभार का विस्तृत उल्लेख किया गया है।

18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर नियम बनाने पर विचार करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर कानूनी और नियामकीय व्यवस्था बनाने पर विचार करने को कहा है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि भारत में काम करने वाले सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मस को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा, भले ही वे विदेश में पंजीकृत हों।

कोर्ट की टिप्पणी थी कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्था केवल दिशानिर्देशों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे वैधानिक रूप देने पर विचार किया जाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जायमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस’ की याचिका पर सुनुवाई के दौरान यह बात कही। सुनुवाई के दौरान सॉलिडिटर जनरल तुषार मेहता ने माता-पिता की सहमति के आधार पर सोशल मीडिया अकाउंट की व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 का भी



उल्लेख किया और कहा कि यह मुद्दा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के दायरे में आ सकता है। याचिका में बच्चों को ऑनलाइन रूमिंग, यौन शोषण, सेक्सटॉर्शन, डिजिटल तस्करी, साइबरबुलिंग और निजी डेटा के दुरुपयोग जैसे खतरों से बचाने की मांग की गई है। हालांकि, फिलहाल 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई देखभाली प्रतिबंध लागू नहीं हुआ है।

गोल्डी बराड़ FBI की मोस्ट वांटेड भगोड़ों की सूची में शामिल, 10 लाख डॉलर तक का इनाम



वांशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भारतीय मूल के गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को अपनी 10 मोस्ट वांटेड भगोड़ों की सूची में शामिल किया है। FBI ने गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने वाले व्यक्ति को 10 लाख डॉलर तक का इनाम देने की घोषणा की है।

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, गोल्डी बराड़ पर लॉरेस बिशनोई ऑर्गनाइज्ड क्राइम रूप से कथित रूप से जुड़े होने का आरोप है। FBI का कहना है कि यह गिरफ्त दक्षिणी कैलिफोर्निया के अलावा अमेरिका और कनाडा में

विभिन्न हिंसक गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल रहा है। FBI के मुताबिक गोल्डी बराड़ पर राजनीतिक और धार्मिक हस्तियों की हत्या, गोलीबारी, हत्या, अपहरण, जबरन वसूली, मारपीट तथा मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी से जुड़े आरोप हैं। उसे हथियारबंद और खतरनाक भगोड़ा बताया गया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार वह उत्तरी अमेरिका में इस नेटवर्क का कथित नेतृत्व करता है।

1 जुलाई को जारी हुआ था फेडरल वारंट

गोल्डी बराड़ के खिलाफ 1 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया ने गिरफ्तारी का फेडरल वारंट जारी किया गया था। उस पर टेक्सास इन्फ्लुएंस एंड करंट ऑर्गनाइजेशन (RICO) साजिश, जमान वसूली के जिक्र आरोबार में दखल देने की साजिश और प्रतिबंधित पदार्थों के वितरण से संबंधित आरोप लगाए गए हैं।



पश्चिम बंगाल: पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन के 15 टिकनों पर ईडी की छापेमारी, मनी लॉड्रिंग मामले में कार्रवाई

कोलकाता, ईएमएन। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन और कुछ अन्य लोगों से जुड़े टिकनों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई कथित मनी लॉड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, ईडी ने कुल 15 टिकनों पर तलाशी ली। यह कार्रवाई एक ऐसे संगठन से जुड़े मामलों में की गई, जो दुर्गा पूजा के पीयूथो आयोजित करता था। जांच एजेंसी को इस संगठन के जरिए कथित तौर पर वित्तीय गड़बड़ी किए जाने की जानकारी मिली है। ईडी का आरोप है कि मासआर्ट (महानिर्माण रेंज मास आर्ट सोसाइटी) नाम की संस्था ने लोगों से बड़ी रकम जुटाई। इस संस्था का नेतृत्व इंद्रनील सेन की पत्नी करती है। आरोप है कि लोगों से पैसे लेते समय यह दावा किया गया कि रकम यूनेस्को द्वारा प्रायोजित किसी संस्था के लिए इस्तेमाल की जाएगी।

सरपंच के पति को 4 हजार रुपये की रिश्तत लेते EOW ने पकड़ा

मंदसौर, एजेंसी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) उज्जैन की टीम ने रिश्ततखोरी के मामले में दलौदा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि अनिल कैथवास को 4 हजार रुपये लेते रीे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार दलौदा निवासी विक्रम सिंह को बैंक से लोन लेना था। लोन प्रक्रिया के लिए उन्हें ग्राम पंचायत से एनओसी की जरूरत थी। आरोप है कि एनओसी देने के एवज में सरपंच प्रतिनिधि अनिल कैथवास ने उनसे 4 हजार रुपये की रिश्तत मांगी। रिश्तत देने के इच्छुक नहीं होने पर विक्रम सिंह ने इसकी शिकायत EOW उज्जैन से की। शिकायत के सत्यापन के बाद टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई।

कृषि उपज मंडी के पास पकड़ा

तय योजना के अनुसार शिकायतकर्ता 4 हजार रुपये लेकर दलौदा की कृषि उपज मंडी के पास पहुंचा। जैसे ही अनिल कैथवास ने उससे रिश्तत की रकम ली, पहले से मौजूद EOW की टीम ने उसे मौके पर पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद टीम ने दलौदा ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचकर दस्तावेजों, सरकारी रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की जांच शुरू की। अनिल कैथवास की पत्नी दुर्गा कैथवास दलौदा ग्राम पंचायत की सरपंच हैं। आरोप है कि पंचायत के कामकाज में अनिल कैथवास सरपंच प्रतिनिधि के रूप में सक्रिय थे।

देश में 20 हजार करोड़ के ट्रैफिक चालान बकाया

सुप्रीम कोर्ट का सुझाव- बिजली बिल में जोड़कर वसूली करें, भुगतान नहीं तो कनेक्शन काटें

नई दिल्ली, एजेंसी । देश में ट्रैफिक ई-चालान की कमजोर वसूली पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सिर्फ चालान जारी करना काफी नहीं, जुर्माना वसूलना भी जरूरी है। बकाया चालान बिजली बिल में जोड़ने का तरीका निकालें। बिजली बिल नहीं चुकाया तो कनेक्शन काटेगा।

कोर्ट को बताया गया कि राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में करीब 45 हजार करोड़ के ई-चालान हुए, इनमें 25 हजार करोड़ वसूले गए हैं जबकि 20 हजार करोड़ के चालान बकाया हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाल और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि बकाया चालान वाले वाहन को परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने की व्यवस्था पर विचार हो। भुगतान तक आरसी नवीनीकरण, ड्रुलीकेट आरसी और वाहन का मालिकाना हक ट्रांसफर रोका जा



सकता है। कोर्ट ने कहा कि फिटनेस और प्रदूषण प्रमाणपत्र भी न दिए जाएं। ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण रोकने या मौजूदा लाइसेंस निलंबित करने पर भी विचार हो। मामला 2012 से चल रही एस. राजशेखरन सड़क सुरक्षा जनहित याचिका में ई-चालान व्यवस्था और वसूली से जुड़ा है।

Supreme Court में चुनाव आयोग विवाद की सुनुवाई अगले हफ्ते

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसले लेते के तरीके को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर नई याचिका को अगले सप्ताह सुनुवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। मामले को मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश किया। याचिका में मुख्य सवाल यह उठाया गया है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त अनेकों चुनाव आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे फैसले ले सकते हैं, जिन्हें आयोग का निर्णय बताया जाए। याचिकाकर्ता को तब है कि चुनाव आयोग एक बहु-सदस्यीय संवैधानिक संस्था है और उसके निर्णय कानून के अनुसार सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर लिए जाने चाहिए।

छत्तीसगढ़ राज्य पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 150 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

दूसरे दिन पुरुषों के बाद महिला वर्ग की स्पर्धाएं, कैलारा जैन बरमेचा ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह

■ यश भारत

भिलाई। छत्तीसगढ़ राज्य एसबीडी पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में प्रदेशभर से पहुंचे खिलाड़ियों के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुष वर्ग के 53, 59, 66, 74 और 83 किलो वजन वर्ग में करीब 150 खिलाड़ियों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। लगातार बारिश के बावजूद खिलाड़ियों का उत्साह कम नहीं हुआ और देर रात तक मुकाबले चलते रहे।

प्रदेशभर के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

प्रतियोगिता में रायगढ़, बिलासपुर, सारंगढ़, चांपा, मनेंद्रगढ़, कोंडागांव, सूरजपुर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, कवर्धा, बलौदाबाजार, मुंगेली, नारायणपुर, बालोद, धमतरी, डल्लूराजहरा, जगदलपुर, बस्तर, भानुप्रतापपुर और कंकिर सहित विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।



पुरुषों के बाद महिला वर्ग की बारी

प्रतियोगिता के दूसरे दिन पुरुषों के 93, 105, 120 और 120 किलो से अधिक वजन वर्ग के मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। इसके बाद महिला खिलाड़ियों की 43, 47, 52, 57, 63,

69, 76, 84 और 84 किलो से अधिक वजन वर्ग की स्पर्धाएं होंगी।

SSP विजय अग्रवाल ने किया उद्घाटन

प्रतियोगिता का शुभारंभ 26 सितंबर को दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के



मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम में बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव अंकुर मिश्रा, अखिलेश मिश्रा, मीडिया प्रभारी मयंक चतुर्वेदी सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीजीपीएलए के कार्यकारी अध्यक्ष तुलसी सोनी ने की। महासचिव कृष्णा साहू,



कैलारा जैन ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला

दूसरे दिन छत्तीसगढ़ पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलारा जैन बरमेचा विशेष रूप से प्रतियोगिता में पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान कर सम्मानित किया।

कोषाध्यक्ष संतोष देवांगन, संघ के पदाधिकारी और निर्णायक भी उपस्थित रहे।

CISF जवान के साथ लिव-इन में रह रही युवती की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

■ यश भारत

दुर्ग। मोहन नगर थाना क्षेत्र के शंकर नगर में 26 वर्षीय अंजलि जगदीश घोड़ेश्वर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। अंजलि पिछले करीब दो वर्षों से CISF जवान करण सिंह के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। करीब 15 दिन पहले ही दोनों शंकर नगर स्थित किराए के मकान में शिफ्ट हुए थे।

सीडियों पर मिला शव, जवान ने परिजनों को दी आत्महत्या की सूचना

27 सितंबर को अंजलि का शव मकान की सीडियों पर पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि घटना के बाद जवान करण सिंह ने अंजलि के परिजनों को फोन कर उसके आत्महत्या करने की जानकारी दी। हालांकि, पुलिस को तत्काल सूचना नहीं

दिए जाने की बात भी सामने आई है।

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

घटना की जानकारी मिलने के बाद अंजलि के परिजनों ने मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का कारण

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही घटनास्थल की परिस्थितियों और CISF जवान से पूछताछ के आधार पर मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है।



बैटरी ट्राइसायकल ने बदली दिनेश की जिंदगी

■ यश भारत

दुर्ग। जिले के नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले आमा कुआँ चौक, पुरेना के रहने वाले दिनेश साहू का जीवन संघर्ष और अदम्य साहस की एक मिसाल है। दोनों पैरों से 80



प्रतिशत दिव्यांग होने के बावजूद, दिनेश ने कभी अपनी परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके। वे अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए एक प्राइवेट नौकरी करते हैं। उनके इरादे जितने बुलंद थे, राह उतनी ही कठिन थी। रोज काम पर आने-जाने में उन्हें भारी शारीरिक कठिनाइयों और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता था। सफर का हर एक कदम उनके लिए एक चुनौती जैसा था, लेकिन वे हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे।

इसी बीच दिनेश को समाज कल्याण विभाग की उस योजना के बारे में जानकारी मिली, जिसके तहत दिव्यांगजनों को उनकी दिव्यांगता के आधार पर आवश्यक सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। उम्मीद की एक नई किरण देखते हुए उन्होंने बिना देर किए समाज कल्याण

विभाग जिला दुर्ग से संपर्क किया। विभाग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह दिन भी आया जिसने दिनेश के जीवन की राह ही बदल दी। सुशासन तिहार के अवसर पर आयोजित एक विशेष शिविर में ग्रामीण विधायक श्री ललित चन्द्राकर के करकमलों से दिनेश साहू को बैटरी चालित ट्राइसायकल प्रदान किया गया। वह पल दिनेश के लिए केवल एक वाहन प्राप्त करने का नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का नया पंख पाने जैसा था। बैटरी चालित ट्राइसायकल मिलने के बाद से अब उन्हें अपने काम पर आने-जाने में किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। सफर अब तकलीफदेह नहीं, बल्कि सुलभ और सहज हो गया है।

आज दिनेश साहू बेहद खुश और आत्म-संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकारी योजनाएं और प्रशासनिक संवेदनशीलता सही समय पर जरूरतमंदों तक पहुंचती हैं, तो वे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती हैं। वे अपनी इस नई आजादी और सुविधा के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और समाज कल्याण विभाग विभाग का आभार व्यक्त किया।



राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने आधी रात को जयस्तम्भ चौक पर नागरिकों संग की चर्चा

■ यश भारत

राजनंदगांव। संसद भवन में मुखर रहने वाले राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे मिलनसार और सहज भी हैं वे रात्रि में 11:00 बजे अपने कार्यक्रम के व्यस्त दौर से लौट रहे थे तभी जय स्तम्भ चौक की चौपाल में बैठे चितपरिचित नागरिकों पर उनकी नजर पड़ी उन्होंने अपनी गाड़ी रूकवाई और सहजता से आकर वे सज्जनों के साथ बैठ गए उन्होंने

सभी का हाल-चाल पूछा ,जनहित के मुद्दों पर चर्चा की, पैकेट वाला फल्लू दाना खाया । इस दौरान 'यश भारत' के मनमोहन शर्मा व 'न्यूज नेशन' के पत्रकार साथी अखिलेश खोन्नगदे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिक विनोद पांडे तथा विष्णु अग्रवाल , रहमान भाई ,हर्ष शर्मा, प्रिंस भाटिया से वे गपशप करते रहे ,उसके बाद उन्होंने गज्जू पान लेले में पान खाया और उपस्थित लोगों के साथ में फोटो खिंचवाया और सब को धन्यवाद कर फिर आडंगा कहकर अपने गंतव्य को रवाना हो गए।

आँगन मिलन सेवा कार्यक्रम में आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों का हुआ सम्मान

केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने सेवा भाव के लिए कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रदान किया प्रमाण पत्र

■ यश भारत

कोण्डागांव । सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिले में सेवा, जनभागीदारी और जनजागरूकता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को ग्राम पंचायत लंजोड़ा के सल्फीपदर स्थित आँगनबाड़ी केंद्र में आँगन मिलन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

कार्यक्रम के दौरान विधायक नीलकंठ टेकाम ने आँगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से निरंतर अपनी सेवाएं दे रही आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को उनके सेवा भाव, समर्पण और योगदान के लिए प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आँगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं बच्चों, माताओं और परिवारों के बीच रहकर पोषण, स्वास्थ्य एवं बाल विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान



करती हैं। उनके निरंतर सेवाभाव और जिम्मेदारी को सम्मानित करना समाज के

लिए प्रेरणादायी है। कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों द्वारा आयोजित चित्रकला

प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया।

विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा के माध्यम से विभिन्न विषयों पर चित्र प्रस्तुत किए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं सम्मान प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ रचनात्मक गतिविधियों में भी सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया गया।

आँगन मिलन कार्यक्रम के माध्यम से एक ओर जहां आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के सेवाभाव को सम्मान मिला, वहीं दूसरी ओर बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने का अवसर मिला। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने भी सेवा और सम्मान की इस पहल की सराहना की।

इस अवसर पर फरसगांव जनपद पंचायत अध्यक्ष मानकू राम नेताम, जनपद सदस्य विजय मरकाम, ग्राम पंचायत लंजोड़ा के सरपंच सुनील नेताम सहित जनप्रतिनिधि, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं, विद्यार्थी तथा ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

यश भारत

दुर्ग व्यूरो चीफ

दैनिक यश भारत समाचार पत्र रायपुर के लिये दुर्ग का ब्यूरो चीफ शमशेर खान को नियुक्त किया गया है। अतः समाचार, प्रेस विज्ञापितियाँ, कार्यक्रमों के लिये आमंत्रण एवं विज्ञापन तथा समाचार पत्र के लिये संपर्क करें।

शमशेर खान

ब्यूरो चीफ 'यश भारत' (दुर्ग)
9691300002



यश भारत

बस्तर संभाग

दैनिक यश भारत समाचार पत्र रायपुर के लिये बस्तर संभाग का ब्यूरो चीफ रवि दुबे को नियुक्त किया गया है। अतः समाचार, प्रेस विज्ञापितियाँ, कार्यक्रमों के लिये आमंत्रण एवं विज्ञापन तथा समाचार पत्र के लिये संपर्क करें।

रवि दुबे

ब्यूरो चीफ 'यश भारत' (बस्तर संभाग)
मो. 7987621085, 9424281645

यश भारत

राजनांदगांव

यश भारत समाचार पत्र द्वारा मनमोहन शर्मा, निवासी जूनी हटरी, राजनांदगांव को जिला ब्यूरो चीफ नियुक्त किया गया है। समाचार, प्रेस विज्ञापित, शासकीय कार्यक्रम, प्रेस आमंत्रण, विज्ञापन एवं समाचार पत्र के लिए संपर्क करें।

मनमोहन शर्मा

जिला ब्यूरो चीफ, यश भारत
मो. 9425246107



22 हजार की रिश्त लेते नागरिक आपूर्ति अधिकारी गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई

■ यश भारत

बलरामपुर । छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी को रिश्त लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने संयुक्त कार्यालय में दबिश देकर नागरिक आपूर्ति अधिकारी विद्यासागर गोपाल को 22 हजार रुपये की रिश्त लेते पकड़ा।

सेवा संकल्प अभियान के तहत भानपुरी में हुआ आँगन मिलन कार्यक्रम

- आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मितानिन को सेवा कार्य के लिए किया गया सम्मानित
- महिलाओं एवं किशोरियों को पोषण आहार और स्वस्थ जीवनशैली की दी गई जानकारी

■ यश भारत

कोण्डागांव । सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिले में सेवा, जन भागीदारी और जनजागरूकता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को ग्राम पंचायत भानपुरी स्थित आँगनबाड़ी केंद्र में आँगन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम की महिलाओं, किशोर बालिकाओं एवं गर्भवती महिलाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत भानपुरी के सरपंच सुभाष पोयाम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर पंच विष्णवी वैद्य एवं कांति मंडावी भी मौजूद रहें। कार्यक्रम के दौरान आँगनबाड़ी कार्यकर्ता सुकलवती वैद्य, सहायिका महेश्वरी मंडावी एवं मितानिन चिंता वैद्य को उनके सेवा कार्य एवं योगदान के लिए प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं एवं किशोर बालिकाओं को



पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में संतुलित आहार के महत्व, स्थानीय एवं मौसमी खाद्य पदार्थों के उपयोग तथा बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक पोषण संबंधी जानकारी साझा की गई। पोषण जागरूकता को व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न प्रकार की हरी एवं मौसमी सब्जियों, फलों तथा स्थानीय स्तर पर तैयार किए जाने वाले पौष्टिक पकवानों का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के माध्यम से महिलाओं को बताया गया कि घर में उपलब्ध स्थानीय खाद्य सामग्री का उचित संयोजन कर स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन तैयार किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं एवं किशोर बालिकाओं को विशेष रूप से अपने आहार में पोषक तत्वों को शामिल करने, नियमित एवं संतुलित भोजन करने तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही आँगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का नियमित लाभ लेने की जानकारी दी गई।

कलेक्टर नूपुर राशि पन के मार्गदर्शन में जिले में पहली बार पाँचों विकासखण्डों के प्राचार्य, शिक्षक एवं विद्यार्थी पहुँचे पीएम केन्द्रीय विद्यालय कोण्डागांव

हेड मेंटर विनायक कोहली के समन्वय में बस्तर की कला के संरक्षण एवं अनुभवात्मक शिक्षा की पहल का शुभारंभ

■ यश भारत

कोण्डागांव । जिले के शैक्षिक इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ा। कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के मार्गदर्शन में चल रही जिला भूगोल प्रयोगशाला परियोजना के अंतर्गत पहली बार जिले के पाँचों विकासखण्डों से चयनित विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक एवं विद्यार्थी एक साथ पीएम केन्द्रीय विद्यालय, कोण्डागांव पहुँचे। उद्देश्य था उस मॉडल को प्रत्यक्ष देखना, जहाँ भूगोल किताब के पन्नों से निकलकर बस्तर की मिट्टी, कला और संस्कृति से जुड़ता है। विद्यालय के प्राचार्य नंदकिशोर वासनिक एवं परियोजना के हेड मेंटर विनायक कोहली ने अतिथियों का स्वागत किया। परिचय और विद्यार्थियों से संवाद के बाद सभी ने सोशल साईंस लैब एवं मिनी बस्तर आर्ट म्यूजियम कॉर्नर का भ्रमण किया, जिसे क्षेत्रीय मीडिया ने छत्तीसगढ़ में अपनी तरह की पहली पहल बताया है।

बस्तर की कला को बचाने की पहल

बस्तर आर्ट म्यूजियम कॉर्नर में विद्यार्थियों से यहाँ प्रदर्शित कलाकृतियों के बारे में प्रश्न पूछे गए। कई वस्तुएँ बच्चों के अपने आस-पास की थीं, फिर भी उनके नाम और कहानियाँ उनके लिए नई थीं। यहीं से इस परियोजना का मूल विचार सामने आया कृ बस्तर और भारत की कला हमारी पहचान है, और उसे सहेजने का सबसे सशक्त माध्यम है उसे शिक्षा से जोड़ना। कला-समेकित शिक्षण परियोजना इसी सोच पर आधारित है,



ताकि बच्चे अपनी धरती की कला को केवल देखें नहीं, बल्कि समझें, अपनाएँ और आगे बढ़ाएँ।

जहाँ भूगोल और बस्तर एक-दूसरे से मिलते हैं

इसके बाद विद्यार्थी समूहों में सोशल साईंस लैब पहुँचे। भूगोल के मॉडल, मानचित्र और ऐतिहासिक मॉडलों के बीच उन्होंने देखा कि बस्तर की मिट्टी,

रसूखदारों के आगे बेबस दिखी खाकी आम जनता और मीडिया से अभद्रता ने बढ़ाई नाराजगी

■ यश भारत

राजनांदगांव। शहर में इस बार गणेश विसर्जन के दौरान पुलिस की लचर कार्यशैली और दोहरी व्यवस्था के चलते आम नागरिकों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। विसर्जन पर्व पर पुलिस का इकबाल कमजोर नजर आया, जहाँ एक ओर रसूखदार समितियों ने नियमों को ताक पर रखकर अपनी झांकियों को घंटों सड़कों पर रोके रखा, वहीं दूसरी ओर पुलिस मूकदर्शक बनी लाचार नजर आई। इस दौरान जाम की स्थिति से जूझते रहे दर्शनार्थियों और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

रसूखदारों के सामने नतमस्तक हुई पुलिस

सूत्रों के अनुसार, शहर के मुख्य मार्ग पर रसूखदार लोगों और कुछ विशेष समितियों ने अपनी झांकियों को मनमाने तरीके से घंटों रोके रखा, जिससे पीछे चल रही अन्य समितियों की झांकियों के साथ यातायात पूरी तरह ठह गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पीछे चल रही समितियों के लोगों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। हैरानी की बात यह रही कि घंटों से बाधित इस व्यवस्था को पटरी पर लाने और रूटों हुई झांकियों को आगे बढ़ाने की हिम्मत कोई भी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी नहीं जुटा पाया।

महिला ट्रेनी IPS पर पत्रकार से अभद्रता का आरोप

विवाद और जाम के इस माहौल के बीच जब शहर के एक फोटो जर्नलिस्ट ने पुलिस की इस लाचारी और मौके पर उपजे तनाव के दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करना चाहा, तो वहाँ तैनात प्रशिक्षित IPS वैशाली जैन ने कथित तौर पर पत्रकार के साथ अभद्रता की। सूत्रों का दावा है कि महिला अधिकारी ने पत्रकार पर दबाव बनाते हुए उसके कैमरे से विसर्जन के दौरान खींची गई



सभी तस्वीरों और सामग्रियाँ डिलीट करवा दीं। वहीं घंटों से जाम लगाए बैठे झांकियों को आगे बढ़ाने या यातायात सुचारू कराने की हिम्मत इस महिला अधिकारी ने नहीं दिखाई, जिसकी चर्चा पूरे शहर में दिनभर होती रही।

डीजे के नियमों की उड़ी धजियाँ, बैरिकेडिंग से बढ़ी मुसीबत

विसर्जन के दौरान सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन के ध्वनि विस्तारक यंत्रों (DJ) के तय मानकों की भी जमकर धजियाँ उड़ीं। रातभर निर्धारित डेसिबल और समयासीमा

के नियमों को ताक पर रखकर डीजे बजाए जाते रहे, लेकिन पुलिस यहाँ भी पूरी तरह बेबस और नतमस्तक नजर आई।

इसके अलावा, पुलिस प्रशासन की ओर से शहर में की गई रूट व्यवस्था भी सवाल के घेरे में है। अधिकांश जगहों पर मुख्य मार्गों को जोड़ने वाली छोटी गलियों और रास्तों को बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह बंद कर दिया गया था। जानकारों का मानना है कि यदि ये रास्ते खुले रहते, तो भीड़ स्वतः डायवर्ट हो जाती और भारी जाम की स्थिति से बचा जा सकता था। रास्तों को बेवजह बंद किए जाने

से शहरवासियों और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

लोगों का कहना है त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और सुगम यातायात की जिम्मेदारी संभालने वाली पुलिस का इस तरह रसूखदारों के आगे नतमस्तक होना और अपनी नाकामी छुपाने के लिए मीडिया पर धाँस जमाना शहर में चर्चा का मुख्य विषय बन गया है। आम जनता अब यह सवाल पूछ रही है कि क्या पुलिस के नियम सिर्फ आम आदमी के लिए हैं और वीआईपी संस्कृति के आगे कानून व्यवस्था पूरी तरह घुटने टेक चुकी है?

विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र (राजनांदगांव) में प्रशासनिक लापरवाही बघेरा कांजी हाउस में भूख से तड़पकर 07 मवेशियों की मौत

रेवाडीह की स्थिति भी दयनीय

■ यश भारत

राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले में प्रशासनिक उदासीनता और भारी लापरवाही का एक बेहद अमानवीय मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय से सटे बघेरा गांव स्थित कांजी हाउस में चारे और पानी की कमी के कारण 7 मवेशियों की तड़प-तड़पकर दर्दनाक मौत हो गई है। इस हृदयविदारक घटना ने स्थानीय प्रशासन और गौवंश की सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है। बघेरा कांजी हाउस की घटना चंदे के पैसे खाने-पीने में खर्च नहीं हुए ग्रामीणों और पूर्व सरपंच राजेंद्र यदु के अनुसार, फसलों को बचाने के लिए लावारिस पशुओं को तार का घेरा बनाकर बघेरा के कांजी हाउस में बंद किया गया था। सूत्र बताते हैं कांजी हाउस के संचालन और मवेशियों के चारे-पानी की व्यवस्था के लिए गांव के सरपंच पति हरीश देशमुख, सचिव राजकुमार देवांगन और ग्राम पटेल दुर्जन लाल देवांगन द्वारा हर घर से 200 रुपये प्रति माह चंदा वसूला जा रहा था। आरोप है कि वसूली गई राशि का उपयोग पशुओं के रख-रखाव में नहीं किया गया। उचित खान-पान न मिलने के कारण शनिवार को और रविवार इन दोनों दिनों में 7 मवेशियों ने दम तोड़ दिया।

बदबू से खुला राज कांजी हाउस के भीतर मृत मवेशियों के शवों से जब इलाके में भारी दुर्गंध फैलने लगी, तब प्रयोगशाला की संरचना एवं जाँच-सूची पर चर्चा हुई, ताकि प्रत्येक विद्यालय अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी प्रयोगशाला तैयार कर सके।

बच्चों की आवाज़, शिक्षकों के प्र

विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए, जिन्हें परियोजना के लिए संकलित किया गया। शिक्षकों ने कक्ष एवं आधारभूत संरचना जैसी व्यावहारिक कठिनाइयाँ रखीं, जिन पर मिलकर समाधान खोजे गए। प्राचार्य ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है शुरुआत करना कृ कर्मियों धीरे-धीरे पूरी होती जाएँगी।

आगे की राह

समापन पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षक एवं हेड मेंटर विनायक कोहली ने परियोजना की दिशा रखते हुए कहा कि बच्चे विद्यालय आकर केवल व्याख्यान सुनकर न लौटें, बल्कि सीखने को अनुभव करें, ताकि जो सीखें वह जीवन भर साथ रहे। जब बस्तर की कला कक्षा का हिस्सा बनेगी, तभी वह सुरक्षित रहेगी कृ और यहीं से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जमीनी स्तर पर साकार होगी।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और महतारी वंदन योजना से मिला आर्थिक संबल

■ यश भारत

कोण्डागांव। राज्य शासन एवं केंद्र शासन द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ लेकर जिले की अनेक महिलाएं अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।

जगहों पर चुपचाप फेंककर मामला दबाने का प्रयास किया गया था। बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ आपराधिक लापरवाही और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत सख्त FIR दर्ज करने की मांग की है।

रेवाडीह कांजी हाउस का हाल भी बद से बदतर

बघेरा की यह घटना अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि जिला मुख्यालय स्थित रेवाडीह के कांजी हाउस से भी इसी तरह की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सूत्र बताते हैं कि नगर निगम द्वारा संचालित होने वाले रेवाडीह कांजी हाउस में भी रोजाना 1 से 2 गायों की मौत हो रही है। कांजी हाउस में घुमंतू गावों को लाकर रख तो दिया जाता है, लेकिन उनके लिए चारा और पानी की न्यूनतम व्यवस्था भी नहीं है, जिसके चलते बेजुबान दम तोड़ने को मजबूर हैं।

बेजुबान जानवरों की बदकिस्मती का आलम यह है कि इस गंभीर हालात को देखने न तो शहर के गौ सेवक पहुँच रहे हैं और न ही कोई प्रशासनिक टीम सुध ले रही है।

स्थानीय लोगों की प्रमुख मांगें

बघेरा गांव के दोषी सरपंच पति, सचिव और ग्राम पटेल के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही जिला प्रशासन को संज्ञान लेते हुए जिले के सभी कांजी हाउसों का अचानक (ऑचक) निरीक्षण करना चाहिए, ताकि अन्य जगहों की असलियत भी सामने आ सके। प्रशासन द्वारा सभी कांजी हाउसों में मवेशियों के लिए तुरंत चारे, पानी और पशु चिकित्सकों की नियमित टीम को तैनात सुनिश्चित की जाए।

कठिन समय में दिव्यांग संगीता को योजनाओं का मिला सहारा

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और महतारी वंदन योजना से मिला आर्थिक संबल

■ यश भारत

कोण्डागांव। राज्य शासन एवं केंद्र शासन द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ लेकर जिले की अनेक महिलाएं अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।



यशोभारत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल	
संपादकीय	
बच्चों के हाथ में मोबाइल बढ़ा तो बचपन हुआ डिजिटल कैद अभिभावकों की जागरूकता से ही मोबाइल की लत पर लग सकता है अंकुश	
आज के समय में मोबाइल फोन जीवन की आवश्यकता बन चुका है। पढ़ाई, जानकारी, संवाद और मनोरंजन से लेकर अनेक जरूरी काम स्मार्टफोन के माध्यम से पूरे किए जा रहे हैं। लेकिन जब यही सुविधा बच्चों की आदत और फिर लत में बदलने लगे तो यह चिंता का विषय बन जाता है। देश में बच्चों और किशोरों के बीच स्मार्टफोन का इस्तेमाल जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसने अभिभावकों और समाज के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। खासकर 10 से 19 वर्ष की उम्र के बच्चे डिजिटल दुनिया में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में 15 से 19 वर्ष के करीब 49 प्रतिशत बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे थे, जो 2023 तक बढ़कर 91 प्रतिशत से अधिक हो गया। यानी तीन वर्ष में उपयोग में लगभग 42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। बच्चों में स्मार्टफोन की पहुंच केवल किशोरों तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार 8 से 18 वर्ष की उम्र के करीब 30 प्रतिशत बच्चों के पास अपना व्यक्तिगत फोन है, जबकि 62 प्रतिशत बच्चे माता-पिता के फोन का इस्तेमाल करते हैं। वर्ष 2026 की शुरुआत तक 10 से 14 वर्ष की उम्र के लगभग 83 प्रतिशत बच्चों की स्मार्टफोन तक पहुंच बताई गई है। यह आंकड़ा वैश्विक औसत से भी अधिक है। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि मोबाइल केवल बच्चों के हाथ में पहुंचने वाली तकनीक नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल उनके व्यवहार, सोच, पढ़ाई, सामाजिक संबंध और सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। बच्चों को मोबाइल देने की शुरुआत अक्सर बहुत सामान्य कारणों से होती है। बच्चा खाना नहीं खा रहा हो, जिद कर रहा हो, रो रहा हो या शरारत कर रहा हो तो उसे शांत करने के लिए मोबाइल हाथ में थमा दिया जाता है। धीरे-धीरे बच्चा मोबाइल को मनोरंजन का सबसे आसान साधन मानने लगता है। माता-पिता भी व्यस्तता के कारण कई बार इस आदत पर तत्काल ध्यान नहीं देते। बच्चे की जिद पूरी करना उस समय आसान समाधान दिखाई देता है, लेकिन यही सुविधा आगे चलकर आदत का रूप ले सकती है। जब बच्चा हर खाली समय मोबाइल पर बिताने लगे और मोबाइल न मिलने पर बेचैनी दिखाए तो अभिभावकों को इसे गंभीर संकेत मानना चाहिए। मोबाइल और इंटरनेट का सही इस्तेमाल बच्चों के लिए ज्ञान और सीखने का माध्यम बन सकता है। समस्या तब पैदा होती है जब स्क्रीन का उपयोग जरूरत से अधिक होने लगे। कई बच्चे प्रतिदिन सात से दस घंटे तक स्क्रीन के सामने समय बिताने लगे हैं। इससे पढ़ाई के लिए मिलने वाला समय प्रभावित होता है और खेलकूद, परिवार के साथ बातचीत तथा सामाजिक गतिविधियों के लिए समय कम हो जाता है। लगातार स्क्रीन पर रहने की आदत बच्चों को वास्तविक दुनिया से दूर कर सकती है। मोबाइल पर मिलने वाला लगातार मनोरंजन उन्हें सामान्य गतिविधियों में कम रुचि लेने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा का पहलू इससे भी अधिक गंभीर है। इंटरनेट की दुनिया में अच्छी सामग्री के साथ ऐसी सामग्री भी मौजूद है जो बच्चों के लिए अनुपयुक्त और नुकसानदेह हो सकती है। (लेखक-कातिलाल मांडोट)	
कड़वे वचन दूध उबल रहा है तो उसे शांत करने के दो ही तरीके हैं या तो उस पर ढंडा पानी डाल दो या फिर गैस बंद कर दो । ठीक इसी तरह सामने वाला अगर क्रोध में उबल रहा है तो उसे शांत करने के दो ही तरीके हैं या तो आप चुप हो जाइये या फिर वहां से हट जाइये । जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है । चुप्पी कई सवालों का जवाब हुआ करती है । कुछ सवालों का जवाब चुप्पी से देना सीखो ।	
आज का राशिफल पंचांग:- 30 सितंबर 2026 दिन-बुधवार, माह- भाद्र सुपुल पक्ष विक्रम संवत् 2083 मेष सु. री. री. रा. मी. मी. कु. मी. कु. धार्मिक स्थल पर समय व्यतीत करने से सुकृत मिलेगा। कोई भूमि संबंधी खरीद-फरोख्त का कार्य हो सकता है। वृष इ. उ. ध. मी. रा. मी. कु. मी. कु. घर में किसी संबंधी के आगमन से आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं। धैर्य से कार्य करें मिथुन मम. की. कु. मी. उ. रा. मी. कु. मी. कु. रुप-पैसे संबंधी लेनदेन को लेकर किसी से वाद-विवाद होने का आशंका है सिंह म. मी. म. मी. म. कु. मी. कु. मी. कु. साझेदारी संबंधी व्यवसाय में पारदर्शिता रखें। नौकरी पेशा लोगों को कोई अधीरटी मिल सकती है। तुला रा. री. कु. र. री. रा. मी. कु. मी. आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करें। स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा उलम दिनचर्या रखें। धनु रे. मी. म. मी. म. रा. मी. कु. मी. दिन उत्साह भर रहेगा आपकी योजना से सभी कार्य सुचारु रूप से होते जाएंगे कुंभ सु. री. मी. मी. मी. कु. मी. कु. बातचीत करते समय अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। इससे संबंध खराब हो सकते हैं।	 ज्योतिषाचार्य षडित लोकेश व्यास

विचार प्रवाह

गाद की सफाई नहीं, नदी का संतुलन जरूरी

नदी में गाद दिखते ही हमारी नजर नदी पर नहीं, गाद पर टिक जाती है। हमें लगता है कि नदी का तल भर गया है, इसलिए पानी रुक रहा है; गाद निकाल देंगे तो नदी गहरी हो जाएगी और बाढ़ का संकट कम हो जाएगा। लेकिन नदी इतनी सरल गणित नहीं है। जिस गाद को हम नदी की समस्या कह रहे हैं, वही गाद नदी के स्वभाव और उसकी यात्रा का हिस्सा भी है।

तो फिर सवाल यह है कि समस्या गाद है या गाद का असंतुलित जमाव? यदि गाद निकालना ही समाधान है तो हर बरसात के बाद नदी फिर क्यों भर जाती है? और यदि गाद नदी के साथ चलने वाली प्राकृतिक तलछट है तो उसे हटाने से पहले यह कौन तय करेगा कि कहाँ से कितनी गाद निकालनी है और कहाँ उसे नदी के साथ बहने देना है?

बिहार में गंगा और उसकी सहायक नदियों को लेकर यह सवाल अब केवल बाढ़ के मौसम का नहीं रह गया है। यह नदी-विज्ञान, जल-प्रबंधन, पर्यावरण और विकास की दिशा का सवाल है। वर्षों से गाद निकालने की मांग उठती रही है। सरकारों ने समितियां बनाईं, विशेषज्ञों ने अध्ययन किए और न्यायिक संस्थाओं के स्तर पर पर्यावरणीय सवाल उठे। फिर भी बहस बार-बार उसी जगह लौट आती है—गाद निकालें या नहीं? असल सवाल इससे आगे का है—गाद क्यों जमा हो रही है और नदी का संतुलन कैसे कायम रखा जाए? 15 सितंबर 2026 को बिहार मंत्रिमंडल ने ‘बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026’ को मंजूरी दी। नीति में नदियों, बराजों और जलाशयों से गाद निकालकर उनकी जलधारण और जलवहन क्षमता बहाल करने तथा निकाली गई गाद का सड़क, रेल, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा और निर्माण कार्यों में उपयोग करने की बात कही गई है।

नीति की जरूरत समझी जा सकती है, लेकिन इसकी सफलता मशीनों से निकलने वाली गाद की मात्रा से नहीं मापी जानी चाहिए। कसौटी यह होनी चाहिए कि गाद निकालने के बाद नदी का व्यवहार क्या बदला? क्या बाढ़ का पानी बेहतर ढंग से निकला? क्या कहीं दूसरे हिस्से में कटाव बढ़ा? क्या तलछट फिर उसी स्थान पर जमा हुई? क्या जलीय जीवन प्रभावित हुआ?

इन सवालों का महत्व इसलिए भी है कि गाद पर बनी पुरानी समितियां हमें पहले ही चेतावनी दे चुकी हैं।

2001 में पूर्व केंद्रीय जल आयोग अध्यक्ष डॉ. बी. के. मिश्र की अध्यक्षता में बनी समिति ने गाा जमाव और बाढ़ के संबंधों की पड़ताल की थी। सरकारी अभिलेखों में दर्ज निष्कर्षों के अनुसार बड़ी नदियों में व्यापक स्तर पर गाद निकासी को सामान्य और आर्थिक रूप से व्यवहार्य समाधान नहीं माना गया। हालांकि विशेष परिस्थितियों वाले कुछ हिस्सों में तकनीकी और आर्थिक अध्ययन के बाद लक्षित गाद निकासी की संभावना स्वीकार की गई।

2016 में केंद्र ने माधव चितले समिति का गठन गंगा में भीमगौड़ा से फरक्का तक गाद प्रबंधन और ड्रेजिंग के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के उद्देश्य से किया। समिति ने नदी के प्रत्येक हिस्से की अलग प्रकृति को समझने पर जोर दिया। तलछट का आवागमन, जमाव, नदी-तल की स्थिति और वार्षिक तलछट बजट जैसे



पहलू इसके केंद्र में रहे।

दोनों समितियों का संकेत स्पष्ट था—पूरी नदी के लिए एक ही नुस्खा नहीं हो सकता।

2017 में बक्सर से फरक्का तक गंगा के हवाई सर्वेक्षण की पहल भी हुई थी। केंद्र की टीम में पूर्व केंद्रीय जल आयोग अध्यक्ष ए.बी. पांड्या और आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ शामिल थे। यह बताता है कि समस्या को लेकर तकनीकी अध्ययन की आवश्यकता सरकार पहले भी स्वीकार करती रही हैं। अब सवाल यह है कि उन अध्ययनों की सीख नई नीति के क्रियाचक्रन में कितनी दिखाई देगी।

फरक्का का प्रश्न भी इसी वैज्ञानिक संदर्भ में देखना होगा। बिहार लंबे समय से गंगा के प्रवाह और तलछट व्यवस्था पर फरक्का के प्रभाव की बात करता रहा है। लेकिन पूरी नदी की जटिलता को किसी एक बराज के खাতে में डाल देना समाधान नहीं है। प्रवाह, ढाल, नदी-तल, सहायक नदियों से आने वाली तलछट, तटों की स्थिति और मानव हस्तक्षेप मिलकर नदी का व्यवहार तय करते हैं। बिहार की नदियां इस जटिलता का जीवंत उदाहरण हैं। हिमालय से उतरने वाली कोसी, गंडक, बामती और दूसरी नदियां भारी मात्रा में तलछट लेकर मैदान में आती हैं। आईआईटी कानपुर के प्रो. राजीव सिन्हा के नदी-विज्ञान संबंधी अध्ययनों ने नदी की आकृति, प्रवाह और तलछट के बीच गहरे संबंध को रेखांकित किया है। नदी का तल स्थिर नहीं है और नदी की धारा भी स्थायी रेखा नहीं है।

यही कारण है कि गाद को केवल हटाए जाने वाले पदार्थ के रूप में देखना गलत होगा। लोअर कोसी में सतत गाद प्रबंधन पर हुए अध्ययनों में इसके संभावित उपयोग को संसाधन के रूप में देखने की संभावना सामने आई है। बिहार की नई नीति में निकाली गई गाद के उपयोग का प्रावधान इसी दिशा में है। लेकिन उपयोग से पहले उसकी गुणवत्ता, संरचना और संभावित प्रदूषण को जांच जरूरी है।

सुल्तानगंज के कवि सुधीर प्रोग्रामर का सुझाव है कि क्षेत्र से निकाली गई गंगा की गाद का इस्तेमाल प्रस्तावित हवाई अड्डा क्षेत्र में भराव के लिए किया जा सकता है।

चुनाव आयोग में विवाद से मतदाताओं के बीच भरोसे का संकट

भारतीय चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद को लेकर आई एक रिपोर्ट के बाद देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों चुनाव आयुक्तों ने मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, नाम हटाने और बहाल करने, फार्म-6 में बदलाव और मतदाता डेटा के प्रबंधन जैसे मामलों पर सवाल उठाए हैं। दोनों आयुक्तों ने मतदाता डेटा और चुनावी सॉफ्टवेयर के केंद्रीकरण को लेकर भी चिंता जताई थी। सीमा खन्ना चुनाव आयोग में आईटी और डिजिटल सिस्टम की प्रमुख अधिकारी हैं। 22 जनवरी 2026 को चुनाव आयोग ने ईसीआईनेट लॉन्च किया गया था। चुनाव आयोग में विवाद ईसीआईनेट और ईआरओनेट के जरिए मतदाता सूची के प्रबंधन को लेकर है। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने सवाल उठाया है कि सीमा खन्ना के नेतृत्व वाले आईटी विभाग ने जमीनी स्तर पर काम करने वाले इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन आफिसर्स (ईआरओएस) की पहुंच और उनके वैधानिक अधिकारों को सीमित कर दिया है। जिस तरह गोवा में ईआरओ वोटर लिस्ट सिस्टम में बदलाव नहीं कर सके। जबकि उनके पास इसकी वैधानिक ताकत थी। लेकिन केंद्र में बैठी सीमा खन्ना का विभाग इस काम को आसानी से कर रहा था। जबकि उनके पास वोटर लिस्ट सिस्टम में बदलाव या छेड़छाड़ का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। इस विवाद का सबसे अहम उदाहरण गोवा का सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, गोवा में 97 मतदाताओं के मामलों की स्थानीय ईआरओ स्तर पर जांच हुई और उन्हें मतदाता सूची में शामिल किए जाने के योग्य पाया गया। लेकिन संबंधित नामों को अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने में सॉफ्टवेयर और डेटाबेस एक्सेस से जुड़ी समस्या सामने आई। ईआरओ इसे मतदाता सूची सिस्टम में डाल ही नहीं पा रहे थे। गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर ने इस समस्या के समाधान और रोलबैक फैसलाली उपलब्ध कराने के लिए 11 से 17 फरवरी 2026 के बीच चुनाव आयोग को आठ बार ईमेल भेजा था। इस कम्प्युनिकेशन में वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश भारती को संबोधित किया गया था और सीमा खन्ना को भी उसकी कॉपी भेजी गई थी। परन्तु केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इस मामले में दोनों चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सेक्रेटरी को भी पत्र लिखा था। दूसरी ओर 18 वर्ष के नए युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोڑने की हर साल होने वाली स्पेशल समरी रिवीजन(एसएसआर) प्रक्रिया 2024 के बाद से लंबित है। हाल के दिनों में निर्वाचन आयोग को लेकर दो स्तरों पर बहस तेज हुई है। पहला सवाल आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर और दूसरा मतदाता सूचियों का एसआईआर को लेकर है। इसके

साथ ही आयोग के भीतर निर्णयों पर मतभेद की खबरों ने भी संस्था की आंतरिक कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर चर्चा को बढ़ाया है।भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जो संविधान के अनुच्छेद 324, वैधानिक नियमों और स्थापित संस्थागत परंपराओं के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। जो एक बहुसदस्यीय संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है।चुनाव कराने वाली संस्था पर उठते सवाल के कारण उसकी विश्वसनीयता कमजोर हुई है। लोकतंत्र में चुनाव केवल मतपत्र या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं है। चुनाव की पूरी व्यवस्था पर नागरिकों का भरोसा लोकतंत्र की वास्तविक ताकत है। दो चुनाव आयुक्तों द्वारा उनकी जानकारी के बिना लिए गए विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर संबंधी निर्णयों पर कई आपत्तियां दर्ज कराई थी।विगत कई वर्षों तक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संसद द्वारा कोई अलग कानून नहीं बनाया था। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में कहा था कि जब तक संसद इस विषय में कानून नहीं बनाती, तब तक नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर होनी चाहिए। न्यायालय ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना था। इसके बाद संसद ने 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल से संबंधित कानून बनाया। इस कानून में चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को

शामिल किया गया। इस व्यवस्था में मुख्य न्यायाधीश को समिति से बाहर कर दिया गया। यही प्रावधान अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती का विषय है। 23 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ में इस मामले पर अलग-अलग मत सामने आए हैं। इसके बाद मामला संविधान पीठ के समक्ष रखे जाने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि नियुक्ति कानून संवैधानिक घोषित हो गया है, बल्कि अब इसकी संवैधानिक वैधता पर बड़े पीठ के स्तर पर विचार का रास्ता खुला है। यहीं लोकतंत्र का मूल प्रश्न सामने आता है कि चुनाव कराने वाली संस्था जितनी स्वतंत्र दिखाई देगी, चुनाव परिणामों और चुनाव प्रक्रिया पर नागरिकों का विश्वास उतना ही मजबूत होगा।मतदाता सूची लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो मतदान केंद्र पर उसकी राजनीतिक भागीदारी संभव नहीं होगी। इसी कारण मतदाता सूची का शुद्धीकरण एक आवश्यक प्रक्रिया है। निर्वाचन आयोग का तर्क रहा है कि मृत, स्थानांतरित, दोहरे या अपात्र नामों को हटाना जरूरी है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान देश भर में ड्राफ्ट रोल से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए जाने से पारदर्शिता पर सवाल खड़ा हो गया है।पात्र नागरिकों के नाम सूची से कट जाने का डर और पूरी सत्यापन प्रक्रिया की जटिलता से आम मतदाता चिंतित हैं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर नागरिक संगठनों और राजनीतिक दलों की ओर से यह चिंता सामने आई कि सत्यापन की कठिन प्रक्रिया के कारण वास्तविक मतदाता कहीं सूची से बाहर न हो जाएं।सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 में बिहार एसआईआर की वैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन मतदाता सूची से जुड़े विवाद ने यह स्पष्ट

क्षेत्र, भूजल, सहायक नदियों, आर्द्रभूमियों और प्राकृतिक प्रवाह से जुड़ी है। गाद निकासी कुछ स्थानों पर जलनिकासी या प्रवाह की बाधा दूर कर सकती है, लेकिन उसे जल-संकट का स्थायी इलाज नहीं माना जा सकता।

इसलिए बिहार की नई नीति को केवल गाद निकालने की नीति नहीं बनने देना चाहिए। इसे नदी और जलग्रहण क्षेत्र के पुनर्स्थापन की व्यापक नीति बनाना होगा। इसके लिए नदी-खंडवार नियमित तलमिति सर्वेक्षण, वार्षिक तलछट बजट, बाढ़ और कम प्रवाह दोनों स्थितियों की मॉडलिंग, गाद की गुणवत्ता की जांच और निकाली गई सामग्री के सुरक्षित उपयोग की व्यवस्था जरूरी है। और सबसे जरूरी है पारदर्शिता। जनता को पता होना चाहिए कि कहाँ से कितनी गाद निकली, क्यों निकली, किस अध्ययन के आधार पर निकली और अगले मानसून में उसका परिणाम क्या रहा। नदी के नाम पर होने वाले हर बड़े हस्तक्षेप का सार्वजनिक लेखा-जोखा होना चाहिए।

मुंगेर के कल्याणपुर की सुमन साहा नदी को केवल जलधारा नहीं मानतीं। उनके अनुसार, चन्द्रियां हमारी पृथ्वी की धर्मनियों के समान हैं।ज नदी की अखिरलता और निर्मलता के लिए तटों के जंगल, मिट्टी, वनस्पति, जैव-विविधता और जलीय जीवों का संरक्षण जरूरी है। वह प्लास्टिक, विषैले रसायनों, औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू कचरे से नदियों को बचाने के लिए सामूहिक और सहभागी प्रयास की जरूरत पर जोर देती हैं।

नदी की यही समग्र समझ आज गाद प्रबंधन की बहस को चाहिए।

क्योंकि नदी की सफाई और नदी का इलाज एक बात नहीं है।

नदी के तल से मशीन चलाकर गाद निकाल देना दिखाई देता है, लेकिन उससे नदी का संतुलन बना या बिगड़—यह तुरंत दिखाई नहीं देता। बाढ़ के बाद नदी की नई धारा, कटे हुए किनारे, बदली हुई गहराई, सूखते आर्द्र क्षेत्र और जलीय जीवों के बदलते आवास ही असली परिणाम बताते हैं।

इसलिए बिहार को अब यह पूछना बंद करना होगा कि कितनी गाद निकालनी है? और पूछना होगा—कहां गाद हटाना जरूरी है, क्यों जरूरी है और हटाने के बाद नदी कैसी होगी? यही फर्क नदी से छेड़छाड़ और नदी प्रबंधन के बीच है।गाद निकालना आसान है, नदी को समझना कठिन।नई नीति की असली परीक्षा यह नहीं होगी कि कितने घनमीटर गाद नदी से बाहर आई। परीक्षा यह होगी कि अगले मानसून में नदी का प्रवाह कितना स्वाभाविक रहा, बाढ़ का पानी कितनी सहजता से निकला, कटाव कहां बढ़ा या घटा, जलीय जीवन कितना सुरक्षित रहा और क्या नदी का तलछट-संतुलन कायम रहा।

नदी को बचाने के लिए उसकी गाद से लड़ना नहीं, उसकी गाद की भाषा समझना जरूरी है।

क्योंकि नदी से गाद निकालकर नदी नहीं बचती। नदी तब बचती है जब उसका प्रवाह, तल, तट, जलग्रहण क्षेत्र, जंगल, आर्द्रभूमि और जीवन—सब साथ बचें। और यही समझ बिहार की गाद नीति को नदी नीति में बदल सकती है।

(लेखक- कुमार कृष्णन)

कर दिया कि सूची सुधार और मताधिकार संरक्षण के बीच संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी भी मतदाता सूची पुनरीक्षण की सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि कितने अपात्र नाम हटाए गए। यह भी देखना होगा कि कितने पात्र नागरिकों के नाम सुरक्षित रहे, कितने नाम हटाए गए लोगों को समय पर सूचना मिली और उन्हें अपना पक्ष रखने तथा अपील करने का वास्तविक अवसर मिला। दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले दस महीनों में आयोग के कुछ निर्णयों, विशेष रूप से एसआईआर से जुड़े मामलों पर कई बार आपत्तियां दर्ज की थी। लोकतांत्रिक संस्थाओं में असहमित विचार-विमर्श और निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि अंतिम निर्णय किस कानूनी आधार पर लिया गया और संबंधित सदस्यों को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध थी या नहीं? वर्तमान विवाद के बाद चुनाव आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि सभी आधिकारिक आदेश, निर्णय और प्रशासनिक निर्देश पूर्ण कानूनी स्वीकृति के साथ तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के तहत निर्धारित वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जारी किया गया है।लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि किसी संस्था की विश्वसनीयता केवल राजनीतिक बयानबाजी के आधार पर तय न हो।बल्कि निर्वाचन आयोग की वास्तविक मजबूती इस बात में होगी कि वह अपने निर्णयों का स्पष्ट कानूनी आधार बताए, राजनीतिक दलों और नागरिकों की आपत्तियों को सुने तथा जहां संभव हो, निर्णय प्रक्रिया से संबंधित पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक करे। लोकतंत्र में चुनाव कराने वाली संस्था की निष्पक्षता का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की राजनीतिक वैधता दांव पर होती है। यदि किसी चुनाव प्रक्रिया पर समाज के एक बड़े हिस्से का भरोसा कमजोर पड़ता है, तो चुनाव परिणाम संवैधानिक रूप से वैध होने के बावजूद उनकी सार्वजनिक स्वीकार्यता पर बहस शुरू हो सकती है। इसलिए निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता किसी एक दल की सुविधा या किसी दूसरे दल की शिकायत का विषय नहीं होना चाहिए। यह प्रत्येक मतदाता का प्रश्न है।क्योंकि लोकतंत्र की विश्वसनीयता केवल इस बात से तय नहीं होती कि चुनाव समय पर हुआ या परिणाम घोषित हो गया। उसकी बुनियाद इस विश्वास पर टिकी होती है कि हर पात्र नागरिक का वोट दर्ज हो, हर वोट का समान मूल्य हो और चुनाव कराने वाली संस्था किसी राजनीतिक सत्ता से ऊपर संविधान के प्रति जवाबदेह हो। यही विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी है।

(लेखक-राज कुमार सिन्हा)

रायपुर

बुधवार, 30 सितंबर 2026

04

दिव्यऋषि मौत मामले में जांच तेज, पांच दिन में आएगी रिपोर्ट

डीबी मॉल के सामने स्ट्रीट लाइट के खंभे से करंट लगने से भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री की हुई थी मौत

भोपाल, यश भारत।

डीबी मॉल के सामने स्ट्रीट लाइट के खंभे से करंट लगने से भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री एवं अधिवक्ता दिव्यऋषि तिवारी की मौत के मामले में प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। भोपाल कलेक्टर की ओर से चार सदस्यीय जांच समिति गठित कर पांच दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। जांच का मुख्य फोकस खंभे में करंट आने के कारण और सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित चूक पर रहेगा।

समिति में अपर कलेक्टर सुमित पांडे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष शर्मा, बिजली विभाग के कार्यपालिका नियंत्रक मोहम्मद जावेद और अधीक्षण अभियंता प्रदीप सिंह चौहान को शामिल किया गया है। समिति घटना के तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की जांच करेगी। स्ट्रीट लाइट के खंभे की स्थिति, विद्युत कनेक्शन, आर्थिंग, रखरखाव और संबंधित विभाग की जिम्मेदारी की भी पड़ताल की जाएगी।



मृतक दिव्य ऋषि तिवारी

नगर निगम की जिम्मेदारी भी जांच के दायरे में

डीबी मॉल के सामने लगा स्ट्रीट लाइट का खंभा नगर निगम भोपाल के अधीन बताया गया है। हादसे के बाद खंभे के रखरखाव और सुरक्षा इंतजामों को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। अब जांच में यह भी देखा जाएगा कि खंभे का नियमित निरीक्षण और आवश्यक रखरखाव हुआ था या नहीं।

वकीलों ने हत्या का केस दर्ज करने की मांग की

मामले में जिला बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने एमपी नगर थाने पहुंचकर जापन सौंपा। उन्होंने घटना को लापरवाही का परिणाम बताते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग की। जिला बार काउंसिल अध्यक्ष देवेन्द्र रावत ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होने तक अधिवक्ता इस मामले को उठाते रहेंगे। प्रशासनिक जांच के साथ पुलिस कार्रवाई भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद हादसे के लिए जिम्मेदारी तय करने और आगे की कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की तस्वीर साफ होगी। सार्वजनिक स्थानों पर लगे स्ट्रीट लाइट और विद्युत खंभों की सुरक्षा को लेकर भी इस घटना ने सवाल खड़े किए हैं।

हॉस्टल के भोजन में कीड़ा मिलने पर छात्रों का हंगामा

भोपाल, यश भारत।

सेज यूनिवर्सिटी भोपाल के कैंपस हॉस्टल में परोसे गए भोजन में कीड़ा मिलने के बाद छात्रों में नाराजगी फैल गई। घटना के बाद छात्रों ने कैंपस में एकत्र होकर विरोध जताया और मेस में भोजन की गुणवत्ता तथा स्वच्छता व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की। जानकारी मिलने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कैंपस इकाई के कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे। अभ्यक्ति कार्यकर्ताओं ने छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की। इसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया और छात्रों को हॉस्टल वापस भेजा गया। अभावित ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मेस की भोजन व्यवस्था की जांच कराने और भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मांग की है। परिषद का कहना है कि हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है। संगठन के अनुसार इससे पहले भी मेस के भोजन को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं।



भोपाल आरटीओ में तकनीकी खामी से कामकाज टप

5 घंटे कतार में खड़े रहे सैकड़ों आवेदक

भोपाल, यशभारत।

भोपाल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में सोमवार को प्रशासनिक अव्यवस्था और तकनीकी खामी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। लर्निंग और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने दूर-दराज से पहुंचे सैकड़ों आवेदकों को भीषण गर्मी के बीच 5 घंटे से अधिक समय तक कतारों में खड़ा रहना पड़ा। सर्वर टप होने के कारण दिनभर कामकाज पूरी तरह टप रहा और शाम को लोग बिना लाइसेंस बनवाए मायूस होकर लौटने को मजबूर हुए। सुबह 10 बजे कार्यालय खुलते ही आवेदकों की लंबी लाइनें लग गई थीं। काम शुरू होते ही तकनीकी खराबी के चलते सर्वर डाउन हो गया। कार्यालय के कर्मचारियों और तकनीकी टीम की कोशिशों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका। दोपहर 3 बजे कर्मचारियों ने आवेदकों को काम न होने की बात कहते हुए अगले दिन आने को कह

दिया, लेकिन इतनी गर्मी के बावजूद कई लोग शाम 5 बजे तक इस उम्मीद में खड़े रहे कि शायद सर्वर चालू हो जाए। हालांकि, सर्वर शाम 5:30 बजे के बाद ही बहाल हो सका, तब तक सभी आवेदक वापस लौट चुके थे।

दूरी और गर्मी ने बढ़ाई परेशानी

आवेदकों ने व्यवस्था पर भारी नाराजगी जताई। लालघाटी से आए दीपक ने बताया कि आरटीओ ऑफिस पहुंचने में ही 1 घंटा लग जाता है, यहां आकर पता चला कि सर्वर बंद है। वहीं बैरागढ़ से आए मनोज शर्मा और नीलबड़ निवासी हर्षद ने कहा कि घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद अब उन्हें कल दोबारा काम-धंधा छोड़कर कतार में लगना पड़ेगा। लाइसेंस विभाग के अलावा इंटरनेट टप रहने से सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ।

ट्रांसपोर्टरों का चक्काजाम, चूनाभट्टी में यातायात हुआ प्रभावित

भोपाल, यश भारत।

परिवहन के नाम पर लगाए जा रहे जुर्माने और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ी अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे ट्रांसपोर्टरों ने सोमवार को चूनाभट्टी थाने के सामने चक्काजाम कर दिया। अचानक किए गए प्रदर्शन के कारण क्षेत्र में यातायात प्रभावित हुआ और स्कूल बसों, यात्री बसों के साथ आम वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोकल ट्रांसपोर्ट जागरूक सहायता समिति के सदस्य 20 सितंबर से विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में परिवहन के नाम पर लगाए जा रहे जुर्माने की व्यवस्था समाप्त करना, मनमाने और भेदभावपूर्ण जुर्माने पर रोक लगाना तथा ट्रांसपोर्ट कारोबार के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू करना शामिल है। चक्काजाम के दौरान चूनाभट्टी क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर जल्द निर्णय ले और ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़ी समस्याओं का समाधान करे। समिति से जुड़े लोगों ने चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जा सकता है।



टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा

भोपाल यश भारत। सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने समेत तीन सूत्रीय मांगों को लेकर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्यप्रदेश का अनिश्चितकालीन आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। मोर्चे ने अब मांग उठाई है कि यदि टीईटी परीक्षा कराई जाती है तो सभी विभागों के कर्मचारियों की भी परीक्षा होनी चाहिए, चाहे अधिकारी कितना ही बड़ा क्यों न हो। मोर्चे की प्रमुख मांगों में सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता समाप्त करना, प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना और ई अटेंडेंस व्यवस्था खत्म करना शामिल है। मोर्चे के अनुसार मांगों को लेकर प्रदेशभर में रैलियां और जापन दिए जा चुके हैं। दिल्ली में भी आंदोलन किया गया था। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से सरकार और विभागीय अधिकारियों से संवाद के बावजूद मांगों का समाधान नहीं हुआ। इसके चलते 27 सितंबर से भोपाल में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया गया है।

13 साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में चार आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा

भोपाल, यश भारत। 13 वर्ष पुराने भ्रष्टाचार के मामले में विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भोपाल ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास और एक-एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने 28 सितंबर को प्रकरण में फैसला सुनाया। मामला अपराध क्रमांक 222/2014 और विशेष प्रकरण क्रमांक 05/16 शासन विरुद्ध हरिहर प्रसाद मिश्रा व अन्य से संबंधित है। अदालत ने हरिहर प्रसाद मिश्रा, अशोक मिश्रा, एपीएस कुशवाहा और संजीव जॉन को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120-बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) और 13(2) के तहत दोषसिद्ध किया। अभियोजन के अनुसार आरोपियों ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर अपराधिक षड्यंत्र करते हुए बंधक कृषि भूमि की नीलामी कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित मूल्य से कम पर कराई। आरोप था कि इस प्रक्रिया में अनियमितता के कारण शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचा।



गांजे के बड़े रैकेट का पर्दाफाश, उड़ीसा तक जुड़े तार

कपड़ों के गट्ठरों के बीच छिपाकर तस्करी कर रहे 6 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में दो महिलाएं कटनी की

दो पिकअप से साढ़े 4 करोड़ का सवा 9 क्विंटल गांजा बरामद

कटनी, यशभारत। उड़ीसा से कटनी आ रही गांजे की एक बड़ी खेप को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दो पिकअप से करीब 9 क्विंटल 19 किलो गांजा बरामद किया है। बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ 59 लाख रुपए आंकी गई है। तस्करी ने गांजे को कपड़ों के गट्ठरों के बीच छिपाकर रखा था। पुलिस ने मामले में दो महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से दो महिलाएं कटनी की रहने वाली हैं, जबकि चार आरोपी ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के बताए गए हैं। यह पूरी कार्रवाई छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में नागपुर चौकी पुलिस ने की है। प्रारंभिक पूछताछ



में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि गांजा ओडिशा से कटनी ले जाया जा रहा था। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक विगत दिवस नागपुर चौकी के सामने वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान ओडिशा नंबर की दो पिकअप को पुलिस



ने रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहनों में रखे कपड़ों के गट्ठरों के नीचे प्लास्टिक के पैकेट और बोरियां मिलीं। जांच करने पर इनमें गांजा भरा हुआ मिला। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। दोनों पिकअप से 200 से ज्यादा पैकेट



गांजा बरामद किए गए। इनका कुल वजन करीब 9.20 क्विंटल और कीमत 4 करोड़ 59 लाख रुपए है। इतनी बड़ी मात्रा में गांजा बरामद होने के बाद पुलिस ने आरोपियों से तस्करी के नेटवर्क को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

दूसरों को अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस खुद बीमार

तीन दिन से सड़क किनारे 'इलाज' का इंतजार

जबलपुर यशभारत। मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए दौड़ने वाली एम्बुलेंस इन दिनों खुद ही इलाज की बात जोह रही है। जबलपुर-कटनी मार्ग पर बेरिया और झगरा गांव के बीच एक एम्बुलेंस पिछले तीन दिनों से सड़क किनारे खड़ी है। बताया जा रहा है कि वाहन में खराबी आने के बाद उसे वहीं खड़ा कर दिया गया, लेकिन अब तक सुधार की कोई ठोस व्यवस्था नहीं हो सकी है। विडंबना यह है कि जिस एम्बुलेंस का काम मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना है, वही तीन दिन से खुद सड़क किनारे खड़ी होकर 'इलाज' की उम्मीद लगाए बैठी है। इधर मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा दिलाने के लिए एम्बुलेंस सेवा को महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन वाहन खराब होने के बाद उसकी सुध लेने में जिम्मेदार विभाग की रफ्तार कुछ धीमी नजर आ रही है।

मरीजों की दौड़ में वाहन ही रुक गया

एम्बुलेंस के लंबे समय तक खड़े रहने से उसकी सेवा प्रभावित होने की स्थिति बन गई है। ग्रामीण और राहगीरों का कहना है कि यदि आपात



स्थिति में इस वाहन की जरूरत पड़ जाए तो परेशानी बढ़ सकती है। विभाग को चाहिए कि खराब वाहन को तत्काल दुरुस्त कर सेवा में लगाया जाए, ताकि मरीजों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उल्लेखनीय है कि जो एम्बुलेंस रोज दूसरों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए दौड़ती है, वह खुद तीन दिन से सड़क किनारे खड़ी होकर विभाग से अपने 'इलाज' की गुहार लगा रही है।

झाड़ू लगाने को लेकर विवाद, दंपति से मारपीट का आरोप

जबलपुर, यश भारत। पाटन थाना क्षेत्र के पौड़ी गांव में घर के सामने झाड़ू लगाने को लेकर हुए विवाद में एक दंपति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना में पति-पत्नी दोनों के सिर में चोट आने की बात सामने आई है। घायल बहादुर प्रसाद झारिया ने धीरत लाल झारिया पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत पाटन थाने में दर्ज कराई गई है। बहादुर प्रसाद के अनुसार उनकी पत्नी घर के सामने झाड़ू लगा रही थीं। इसी दौरान सामने से धीरत लाल झारिया के परिवार की बेटीयां वहां से गुजर रही थीं। झाड़ू लगाने की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। बहादुर प्रसाद ने बताया कि घटना के समय वह पड़ोस में बैठे थे। पत्नी के साथ विवाद होता देखकर वह उन्हें बचाने के लिए मौके पर पहुंचे। आरोप है कि इसी दौरान धीरत लाल ने उन्हें भी लाठी से मार दिया। घटना में दोनों के सिर में चोट आई है।



उज्जैन घटनाक्रम के बाद राजधानी में हाई अलर्ट संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात, सोशल मीडिया पर पैनी नजर

भोपाल, यशभारत।

उज्जैन में हुए हालिया घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए भोपाल पुलिस पूरी तरह सतर्क और अलर्ट मोड पर आ गई है। शहर में शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने राजधानीभर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि शहर के सभी थाना प्रभारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। राजधानी के सभी संवेदनशील और अति-संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस बल द्वारा लगातार पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही पुलिस की विशेष साइबर टीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की गहन निगरानी कर



रही है। भड़काऊ पोस्ट, अफवाहों और माहौल बिगाड़ने वाली सामग्री पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने शहर के सभी सामाजिक, धार्मिक और नागरिक संगठनों से संवाद स्थापित

कर शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने का आग्रह किया है।



विराट कोहली का नया अवतार कैफ बोले, खून के आंसू पिए, अब कोई छू नहीं सकता



नई दिल्ली (ईएमएस)। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने हाल ही में सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नए अवतार की जमकर सराहना की है, जिसके बाद कोहली ने तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में एक तूफानी शतक जड़ा। कैफ ने कहा कि पिछले साल कोहली को संन्यास लेने की सलाह देने वाले लोग अब उन्हें छुने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। 37 वर्षीय कोहली ने रविवार को 88 गेंदों में नाबाद 139 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 9 छक्के शामिल थे। यह पहली बार था जब उन्होंने एक वनडे पारी में 9 छक्के लगाए। उनकी इस विस्फोटक पारी की बदौलत भारत ने 296 रनों का लक्ष्य 41.4 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया।

कैफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में उस समय को याद किया जब अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया दौर पर लगातार दो वनडे मैचों में शून्य पर आउट होने के बाद कोहली आलोचकों के निशाने पर आ गए थे। उस वक्त कई लोगों ने उन्हें संन्यास लेने की सलाह तक दे डाली थी। हालांकि, कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में तीसरे वनडे में नाबाद 74 रन बनाकर आलोचकों का मुह बंद कर दिया था। कैफ ने बताया कि उस घटना के बाद से कोहली ने कुल 11 वनडे पारियां

खेली हैं और 900 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें चार शानदार शतक शामिल हैं। कैफ ने टिप्पणी की कि कोहली अब एक बिल्कुल अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। उनकी वर्तमान आक्रामक शैली इस नए अवतार का प्रमाण है।

पूर्व बल्लेबाज ने कोहली के उतार-चढ़ाव भरे 18 साल के करियर पर प्रकाश डालते हुए कहा, कोहली ने खून के आंसू भी पिए हैं। कैफ ने जोर देकर कहा कि जब कोहली का बल्ल चलाता है, जो उनका शस्त्र है, तो किसी की मजाल नहीं कि उन्हें छू पाए। उन्होंने कोहली की दृढ़ता की सराहना की, जो अब केवल वनडे प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वे टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं। कैफ ने विराट कोहली के आईपीएल करियर का भी जिक्र किया, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने लगातार दो बार चैंपियन बनकर अपना दबदबा कायम किया और कोहली आईपीएल 2026 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे।

कैफ ने कहा कि कोहली युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा हैं। उन्होंने युवाओं को कोहली से फिटनेस, भूख, तपस्या, कड़ी मेहनत और लगातार अपने मुकाम को बनाए रखने की सीख लेने की सलाह दी।

वर्ल्ड कप 2027 को लेकर आई बड़ी खबर, एक अक्टूबर को केपटाउन में होगा शेड्यूल का ऐलान

नई दिल्ली, एजेंसी। ODI क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट को लेकर अहम तारीख सामने आ गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC और क्रिकेट साउथ अफ्रीका यानी CSA जल्द ह्छदु वर्ल्ड कप 2027 के शेड्यूल का ऐलान करेंगे। टूर्नामेंट के शेड्यूल के ऐलान की तारीख और शहर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। 2027 का ODI वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाएगा। टूर्नामेंट की शुरुआत 2 अक्टूबर 2027 को होने की उम्मीद है,

अक्टूबर को केपटाउन में 2027 ODI वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान करेंगे। यह कार्यक्रम टूर्नामेंट के शुरू होने से ठीक एक साल पहले होगा। इसी मौके पर वर्ल्ड कप के टिकटों के लिए बलेट प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, जिसके तहत फैंस टिकट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। 2027 का ODI वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाएगा। टूर्नामेंट की शुरुआत 2 अक्टूबर 2027 को होने की उम्मीद है,



जबकि फाइनल 21 नवंबर को खेला जाएगा। यानी क्रिकेट फैंस को करीब डेढ़ महीने तक ODI क्रिकेट का रोमांच देखने को

और जिम्बाब्वे को सीधे जगह मिलेगी, जबकि बाकी आठ टीमों ICC की ODI रैंकिंग के आधार पर क्वालीफाई करेंगी। मौजूदा स्थिति में भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश रैंकिंग के जरिए जगह बनाने की स्थिति में हैं।

4 टीमों क्वालीफाईंग टूर्नामेंट के जरिए करेंगी एंट्री-साउथ अफ्रीका के मेजबान होने की वजह से रैंकिंग में 9वें स्थान पर मौजूद बांग्लादेश को भी सीधे क्वालीफिकेशन मिल जाएगा। वहीं, वेस्टइंडीज को क्वालीफायर के रास्ते से वर्ल्ड कप में जगह बनानी होगी। चार अन्य टीमों क्वालीफाईंग टूर्नामेंट के जरिए मुख्य प्रतियोगिता में पहुंचेंगी। शेड्यूल जारी होने के दौरान इन टीमों को फिलहाल क्वालीफायर 1, 2, 3 और 4 के नाम से शामिल किया जाएगा। ICC 1 अक्टूबर को वर्ल्ड कप टिकटों के लिए बलेट प्रक्रिया भी शुरू करेगा। हालांकि, 1 अक्टूबर से टिकटों की सीधे खरीदारी शुरू नहीं होगी। फैंस को पहले टिकट बलेट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

पीएम मोदी ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को दी बधाई

नई दिल्ली, एजेंसी। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। एथलेटिक्स में कई भारतीय खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। पुरुषों की लॉन्ग जंप स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने सिल्वर मेडल जीता। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि उनकी शानदार छलांग ने उन्हें पोलिडियम तक पहुंचाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी श्रीशंकर को बधाई देते हुए उनके कौशल, मेहनत और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की।

पुरुषों की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में भारत ने एक साथ दो पदक हासिल किए। यशवीर सिंह ने सिल्वर मेडल, जबकि रोहित यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। यशवीर सिंह ने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सिल्वर



मेडल हासिल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए इसे भारतीय एथलेटिक्स के लिए शानदार परिणाम बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एशियन गेम्स के पोलिडियम पर दो भारतीय जैवलिन थ्रोअर का होना देश के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारत के इस 'खबल पोलिडियम' प्रदर्शन की सराहना की। महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में पारुल



चौधरी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सफलता की सराहना करते हुए कहा कि उनका प्रदर्शन उभरते हुए एथलीट्स के लिए प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी मुरली श्रीशंकर को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी। भारतीय खिलाड़ियों के लगातार शानदार प्रदर्शन से एशियन गेम्स में देश का पदक अभियान मजबूत हुआ है। इन उपलब्धियों से युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी।

रंग संसार

मैं जैकी दादा के साथ काम करने को लेकर काफी नर्वस थीं: करिश्मा कपूर

मुंबई (यशभारत)। अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने मशहूर एक्टर जैकी श्राॅफ के साथ काम करने का एक दिलचस्प अनुभव साझा किया है। उन्होंने जैकी श्राॅफ के साथ 1992 में रिलीज हुई फिल्म पुलिस ऑफिसर में काम किया था। करिश्मा ने बताया कि यह उनके करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक थी, और उस वक्त वह महज 17 साल की थीं, जिसके चलते एक बड़े स्टार के साथ काम करने को लेकर वह काफी नर्वस थीं। यह खुलासा तब हुआ जब जैकी श्राॅफ इंडियाज बेस्ट डॉसर्स सीजन 5 में बतौर गेस्ट शामिल हुए और शो की जज करिश्मा कपूर ने उनके साथ काम के अनुभव को याद किया। करिश्मा ने जैकी श्राॅफ से मुलाकाब होते हुए कहा, मुझे नहीं पता जग्गू दादा, आपको याद है या नहीं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने आपके साथ एक फिल्म की थी, जिसका नाम पुलिस ऑफिसर था। यह मेरी शुरुआती फिल्मों में से एक थी। बहुत पहले की बात है, तब मैं सिर्फ 17 साल की थी। यह प्रेम कैदी के बाद की बात है।

करिश्मा ने आगे उस फिल्म के एक गाने का जिक्र किया, जिसने उन्हें काफी घबरा दिया था। उन्होंने कहा, उसमें एक गाना था देखो ये लड़की करंट मारती है। यह बहुत बड़ा गाना था, जिसमें काफी सारे डॉसर्स थे। मुझे लगता है कि यह पहली बार था जब मैंने इतने सारे डॉसर्स और किसी बड़े स्टार के साथ काम किया था। इसलिए मैं काफी डरी हुई और नर्वस भी थी। उस उम्र में एक बड़े सेट पर इतने सारे लोगों के साथ काम करना किसी भी नए कलाकार के लिए स्वाभाविक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। करिश्मा ने जैकी श्राॅफ के साथ काम करने को अपने लिए सम्मान और खुशी की बात बताया। उन्होंने कहा, आपके साथ काम करना मेरे लिए हमेशा खास रहेगा। उनकी इन बातों से पता चलता है कि जैकी श्राॅफ ने उस युवा अभिनेत्री के साथ किस तरह का सहयोगपूर्ण माहौल बनाया होगा। वहीं जैकी श्राॅफ ने भी करिश्मा कपूर की जमकर तारीफ की।

उन्होंने करिश्मा को एक शानदार एक्ट्रेस बताते हुए कहा कि वह एक मल्टीटैलेंटेड कलाकार हैं और कुछ भी कर सकती हैं। जैकी श्राॅफ ने कहा, एक शानदार और प्यारी महिला के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान और खुशी की बात है।



हेली शाह का नया फेस्टिव सॉन्ग गलगोटो रिलीज

मुंबई (यशभारत)। ओटीटी शो चुंबक में अपने कॉमेडी रोल से दर्शकों का मनोरंजन करने के बाद, अब एक्ट्रेस ने गाने के बारे में प्रतिभाशाली एक्ट्रेस हेली शाह एक बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रही हैं। हेली शाह का नया फेस्टिव सॉन्ग गलगोटो रिलीज हो गया है, जिसे गाना तौर पर आगामी नवरात्र सेलिब्रेशन से पहले जारी किया गया है। गलगोटो गाने में हेली शाह और देवर्षि शाह की जोड़ी दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती नजर आ रही है। इस गाने को मोनाली ठाकुर, पार्थ ओझा और सुहनि अभ्यंकर जैसे लोकप्रिय गायकों ने अपनी आवाज दी है, जिससे इसमें एक अलग ही ऊर्जा का संचार हुआ है। गलगोटो को लेकर

हेली शाह भी बेहद उत्साहित हैं और उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। एक्ट्रेस ने गाने के बारे में बात करते हुए कहा, इसे सुनते ही किसी का भी उठकर डांस करने का मन करने लगता है। इस गाने की शूटिंग का पूरा एक्सपीरियंस काफी एनर्जी से भरा हुआ था। मैं चाहती हूँ कि लोग इस गलगोटो गाने में हेली शाह और सेलिब्रेट करें और इसे खूब एंजॉय करें। हेली ने आगे बताया कि गाने का म्यूजिक वीडियो भी पूरी तरह से फेस्टिव फील देता है। इसमें तेज बीट्स, एनर्जेटिक म्यूजिक और कलरफुल विजुअल ट्रीटमेंट का खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है।



रिति तिवारी के पास रेंज रोवर से लेकर बड़े-बड़े ब्रांड की गाड़ियां हैं: एकम बावा

मुंबई (यशभारत)। आजकल बिग बॉस-20 में भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी की बेटी रिति तिवारी अपनी साथी प्रतिभागियों के साथ बहस के दौरान आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल करने एवं अन्य बयानों के कारण तीखी आलोचना का सामना कर रही हैं। रिति की मां रानी तिवारी के दूसरे पति और पंजाबी गायक एकम बावा ने उनके इन बयानों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। इंस्टाग्राम पर एकम बावा ने एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि वे रिति को बहुत करीब से जानते हैं और उनके दावों में सच्चाई नहीं है। एकम बावा ने रिति के उस बयान पर सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें हर महीने सिर्फ 25,000 रुपये पॉकेट मनी मिलती है। एकम ने अपनी बात को पुष्टा करते हुए कहा, मैं 2020 से लेकर 2025 तक रिति तिवारी के घर पर रहता था। रिति की मां और मैं 2020 से लेकर 2022 तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे, फिर 2022 में हमारी शादी हो गई। इस व्यक्तिगत जुड़ाव के आधार पर उन्होंने रिति की जीवनशैली का विस्तृत खुलासा किया। वीडियो में एकम बावा कहते हैं,



रिति तिवारी का मैं, आप सभी को सच बताता हूँ कि उनके पास 4 से 5 लाख रुपये तक के हैंडबैग हैं, रेंज रोवर से लेकर बड़े-बड़े ब्रांड की गाड़ियां



अपने म्यूजिक वीडियोज को लेकर चर्चा में अविका गौर

मुंबई (यशभारत)। टीवी एक्ट्रेस अविका गौर इन दिनों अपने म्यूजिक वीडियोज को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। बालिका वधू जैसे सुपरहिट सीरियल से घर-घर में पहचान बनाने वाली अविका हाल में दो अलग-अलग गानों बुखार और जालिमा में नजर आई हैं। इस बारे में अविका का कहना है कि म्यूजिक वीडियोज उन्हें अलग-अलग तरह के किरदार, लुक और इमोशंस एक्सप्लोर करने की असीमित आजादी देते हैं, जो उन्हें एक कलाकार के रूप में संतुष्टि प्रदान करती है। बुखार एक पंजाबी गाना है, जिसे विकी संधू ने अपनी आवाज दी है और उन्होंने ही इसके लिरिक्स भी लिखे हैं। इस गाने का म्यूजिक मिक्स सिंह ने दिया है। बुखार के म्यूजिक वीडियो में अविका का स्टाइलिश और मॉडर्न अवतार देखने को मिला, जिसने उनके फैंस को खूब पसंद आया। वहीं, दूसरा गाना जालिमा में अविका पंजाबी सिंगर, कंपोजर और लिरिस्ट कुलविंदर बिष्णू के साथ नजर आईं। पंजाब के खूबसूरत लोकेशन पर शूट किए गए इस गाने में दोनों की जोड़ी की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब लुभा रही है। जालिमा गाना 22 सितंबर को रिलीज हुआ था और तब से इसे लगातार दर्शकों का प्यार मिल रहा है। अविका ने बात करते हुए अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा, जब आप जिस चीज पर काम करते हैं, वह लोगों से जुड़ने लगती है तो बहुत अच्छा महसूस होता है। बुखार और जालिमा एक-दूसरे से काफी अलग हैं और यही चीज इस फेज को मेरे लिए और एक्साइटिंग बनाती है।

हैं। इन गाड़ियों में तो डीजल ही 2 से लेकर 3 हजार तक का पड़ता है। इसके साथ ही, इनकी स्पोर्ट्स कंपनी भी है, जिसका टर्नओवर बहुत कमाल का होता है और कई क्रिकेटर्स उससे जुड़े हैं, तो उसका रुपया कहा जाँएगा और फिर मुंबई में कई प्लैटस्ट है। एकम बावा ने रिति तिवारी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वे लोगों को झूठ बोलना बंद करें। उन्होंने बिग बॉस में उनके व्यवहार पर भी टिप्पणी की और कहा, रिति तिवारी लोगों को पाल बनाना बंद कीजिए और बिग बॉस में जाकर लोगों को गालिया भी न दें। गायक ने रिति तिवारी की मां रानी के बारे में भी कुछ गंभीर बातें कहीं। उन्होंने कहा, रिति तिवारी की मां के बारे में बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उन्होंने मेरे साथ जो किया है, वैसा भगवान किसी के साथ न करें। एकम बावा ने अपनी सार्वजनिक छवि पर भी बात की और बताया, मैं सोशल मीडिया पर लाइव नहीं आता हूँ और न ही इतनी वीडियो बनाता हूँ, चाहें तो हमारे दर्शक मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। हालांकि, कभी-कभी बनाकर डाल देता हूँ। मैं बस काम से मतलब रखता हूँ।

कृषि मंत्री के लगातार प्रयासों से छत्तीसगढ़ के किसानों को केंद्र की बड़ी सौगात

■ यश भारत

रायपुर। राष्ट्रीय कृषि मंत्रियों के सम्मेलन ‘रबी अभियान 2026’ के अवसर पर 28-29 सितंबर को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र और किसानों के हित में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत कुल 181.99

करोड़ रुपये की द्वितीय मद की राशि जारी किए जाने की जानकारी देते हुए मंत्री रामविचार नेताम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। गौरतलब है कि कृषि मंत्री राम विचार नेताम के निरंतर प्रयासों से प्रदेश के किसानों को समृद्धि मिल रही है।

भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को जारी 181.99 करोड़ रुपये में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 91.20 करोड़ रुपये तथा कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत 90.79 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस राशि से राज्य में



कृषि से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों को गति मिलेगी तथा किसानों को इसका लाभ प्राप्त होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने तथा राज्यों के साथ मिलकर कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ सरकार इस राशि का समयबद्ध एवं प्रभावी उपयोग करते हुए राज्य के किसानों तक

इसका अधिकतम लाभ पहुंचाएगी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कृषि विकास और किसानों के हित में जारी इस राशि के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में कृषि क्षेत्र को नई गति मिल रही है। प्राप्त राशि का उपयोग कृषि क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने तथा किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने की दिशा में

किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि रबी अभियान 2026 के तहत देशभर के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन 28 एवं 29 सितंबर को आयोजित किया गया। सम्मेलन में कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों, किसानों के हित में संचालित योजनाओं तथा कृषि विकास की आगामी रणनीतियों पर चर्चा की जा रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम की केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य मुलाकात हुई।

छत्तीसगढ़ में विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप मामलों की समीक्षा के लिए समीक्षा प्राधिकरण गठित

■ यश भारत

रायपुर। गृह विभाग ने विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्यों की स्वतंत्र समीक्षा तथा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकार को अनुशंसा करने के लिए गठित समीक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति की है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार गौतम चौरडिया, अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को समीक्षा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 45 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा 9 अप्रैल 2026 को समीक्षा प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। अब इस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में गौतम चौरडिया की नियुक्ति की गई है। समीक्षा प्राधिकरण का उद्देश्य जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्यों की स्वतंत्र समीक्षा करना तथा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकार को आवश्यक अनुशंसा करना है। प्राधिकरण द्वारा संबंधित मामलों में उपलब्ध साक्ष्यों और जांच प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी।

रसोइयों के मानदेय भुगतान की मुरिकल होगी दूर, 117 करोड़ के पुनर्विनियोजन को वित्त विभाग की मंजूरी

■ यश भारत

रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत रसोइयों के मानदेय की टॉपअप राशि के लिए 117 करोड़ रुपये के पुनर्विनियोजन को प्रशासकीय स्वीकृति दी है। विभागीय आदेश के अनुसार, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का संचालन जुलाई 2026 से एसएनए-स्पर्श के माध्यम से किया जा रहा है। इसके तहत रसोइयों के मानदेय भुगतान के लिए टॉपअप राशि के लिए पृथक से राज्य आयोजना मद में प्रावधान है। राज्य आयोजना मद में प्रावधानित राशि को केंद्र प्रवर्तित योजना के राज्यांश मद में पुनर्विनियोजित किया गया है। आदेश में संबंधित बजट शीर्षों के बीच 102 करोड़, 10 करोड़ और 5 करोड़ रुपये के पुनर्विनियोजन का विवरण दिया गया है। यह पदले से प्रावधानित राशि का पुनर्विनियोजन है। विभाग ने राशि का मदवार व्यय विवरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।

अब घर बैठे 1-क्विक में कराएं जमीन का सीमांकन, तहसील दफ्तरों के चक्करों से मिली आजादी

■ यश भारत

रायपुर। राज्य में नागरिक सुविधाओं को सुगम, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। प्रदेश के राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग ने जमीन के सीमांकन संबंधी प्रकरणों के त्वरित और सहज निपटारे के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर लागू कर दिया है। इस आधुनिक व्यवस्था के शुरू होने से अब आम नागरिकों को अपनी ही जमीन की नाप-जोख या सीमांकन कराने के लिए तहसील कार्यालयों के बार-बार चक्कर काटने की मजबूरी से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। राज्य का कोई भी नागरिक अब अपने घर अथवा नजदीकी केंद्र से ही सीमांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेगा।

पुरानी व्यवस्था के तहत जमीन का सीमांकन कराने के लिए आवेदकों को खुद तहसील दफ्तर जाकर आवेदन जमा करना पड़ता था। इतना ही नहीं,



आवेदन के बाद फाइल किस स्तर पर अटकती है, कार्रवाई पूरी होने में देरी क्यों हो रही है या किन कारणों से मामला लंबित है-इसकी सही जानकारी समय पर न मिल पाने के कारण लोगों को हफ्तों और महीनों तक दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे।

नवीन व्यवस्था ने इस पूरी जटिल प्रक्रिया को बेहद सुलभ बना दिया है। अब नागरिक अपनी सुविधा अनुसार

लोक सेवा केंद्र (बैबू), सेवा सेतु या फिर राजस्व विभाग के सिटीजन पोर्टल के माध्यम से सीधे ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

जैसे ही कोई आवेदक ऑनलाइन फॉर्म जमा करेगा, वह सीधे संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार की लॉगिन आईडी में प्राप्त हो जाएगा और निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही सीमांकन

संजू की स्वर्णिम जीत पर उप मुख्यमंत्री साव ने थपथपाई पीठ, कहा छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को मिलेगा उनके अनुभव का लाभ

■ परिजनों के साथ उप मुख्यमंत्री साव से मिली संजू देवी, भारतीय महिला कबड्डी टीम के गोल्ड मेडल तक का सफर किया साझा

■ यश भारत

रायपुर। एशियन गेम्स-2026 में महिला कबड्डी में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी संजू देवी ने रायपुर लौटने के बाद उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव से मुलाकात की। श्री साव ने अपने नवा रायपुर स्थित शासकीय निवास

कार्यालय में हुई मुलाकात के दौरान संजू देवी की उपलब्धि पर उनका अभिनंदन कर हौसला बढ़ाया। उन्होंने संजू की माता श्रीमती अमरीका बाई और पिता रामजी का भी अभिनंदन किया।

उप मुख्यमंत्री साव ने संजू देवी को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने भारत के साथ छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ लोगों को भी गौरवान्वित किया है। उन्होंने संजू से एशियन गेम्स के अनुभव और उनकी टीम के स्वर्ण पदक तक के अजेय सफर की जानकारी ली। श्री साव ने उनसे प्रतियोगिता के दौरान मिले अनुभवों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के



विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की। श्री साव ने संजू का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि एशियन गेम्स जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिला उनका अनुभव केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित नहीं रहेगा। इस

अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ के अन्य खिलाड़ियों को भी मिलेगा। श्री साव से संजू देवी की मुलाकात के दौरान खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार और संचालक श्रीमती आकांक्षा शिक्षा खलखो भी मौजूद थीं।

नदी घाट की सफाई कर सकोला के ग्रामीणों ने दिया जल संरक्षण का संदेश

■ यश भारत

रायपुर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जीपीएम जिले के पेण्ड्रा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत सकोला में जल संरक्षण और स्वच्छता को लेकर विशेष जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जल संसाधन विभाग तथा ग्रामीण पेयजल स्रोतों की जांच एवं प्रांत जल सुरक्षा संवाद जैसी गतिविधियां संचालित की गईं। इस दौरान ग्रामीणों ने जल स्रोतों को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने

के साथ जल संरक्षण में सक्रिय भागीदारी का सामूहिक संकल्प लिया।

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों एवं संबंधित विभागीय अमले ने नदी घाट तथा आसपास के जल स्रोतों की साफ-सफाई की। स्वच्छता गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीणों को समझाया गया कि जल स्रोतों की स्वच्छता सीधे तौर पर सुरक्षित पेयजल और स्वस्थ जीवन से जुड़ी है। नदी, तालाब, कुएं एवं अन्य पारंपरिक जल स्रोतों के आसपास कचरा नहीं डालने तथा नियमित साफ-सफाई बनाए रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। जल जन चौपाल के दौरान ग्रामीणों से जल के विवेकपूर्ण उपयोग और उपलब्ध जल संसाधनों के संरक्षण



पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि पानी का उपयोग आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए तथा वर्षा जल, नदी-तालाब और अन्य प्राकृतिक

एवं पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए सामुदायिक प्रयास जरूरी हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल स्रोतों की जांच भी की गई। ग्रामीणों को

सुरक्षित पेयजल के महत्व की जानकारी देते हुए जल स्रोतों की नियमित निगरानी, स्वच्छता और संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की अपील की गई। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपने आसपास के पेयजल स्रोतों को स्वच्छ रखने और किसी भी प्रकार के प्रदूषण से बचाने में सहयोग करने का आग्रह किया। ग्राम जल सुरक्षा संवाद के दौरान जल संरक्षण एवं संवर्धन में ग्रामीणों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि जल स्रोतों का संरक्षण केवल विभागीय गतिविधि नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की साझा जिम्मेदारी है। ग्रामीणों की नियमित सहभागिता से प्राकृतिक और पारंपरिक जल स्रोतों को लंबे समय तक सुरक्षित

रखा जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में ग्रामवासियों ने जल की प्रत्येक बूंद के महत्व को समझते हुए जल स्रोतों को स्वच्छ एवं संरक्षित रखने का सामूहिक संकल्प लिया। ग्रामीणों ने जल का अपव्यय रोकने, नदी घाट एवं अन्य जल स्रोतों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने तथा जल संरक्षण और संवर्धन की गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता निभाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित यह कार्यक्रम स्वच्छता, जल संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता को एक साथ जोड़ते हुए ग्रामीणों में जल के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने का माध्यम बना।

महतारी वंदन की राशि का संदेश आते ही खिल उठता है रेखा का चेहरा बच्चों की पढ़ाई और सिलाई के सामान के खर्च की चिंता हुई कम, हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता से बढ़ा आत्मविश्वास

■ यश भारत

रायपुर। मोबाइल फोन पर महतारी वंदन योजना की राशि खाते में आने का संदेश मिलते ही ग्राम सारबहरा निवासी श्रीमती रेखा कैवर्त के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। परिवार की सीमित आय के बीच हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता ने उन्हें घरेलू जरूरतों और बच्चों की पढ़ाई से जुड़े खर्चों को संभालने में सहायता दी है। अब बच्चों की दृष्टान फीस हो या अपनी सिलाई की दुकान के लिए फाल-अस्तर खरीदने का खर्च, इन जरूरतों के लिए उन्हें पहले जैसी चिंता नहीं करनी पड़ती।

42 वर्षीय श्रीमती रेखा कैवर्त गरीबी

रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार से हैं। गौरेला विकासखंड के ग्राम सारबहरा में वे छोटे स्तर पर टेलरिंग का काम करती हैं। इसी आमदनी से वे अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभालती हैं। उनके परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा है और सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा, घर का खर्च और सिलाई के काम के लिए पैसे की आवश्यकता सामग्री जुटाना उनके लिए लंबे समय से चुनौती रहा है।

रेखा बताती हैं कि पहले महीने के घरेलू खर्च और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी जरूरतों को लेकर उन्हें अक्सर चिंता रहती थी। सिलाई के काम के लिए फाल-अस्तर जैसी सामग्री खरीदने के लिए भी

पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती थी। ऐसे में महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता उनके लिए उपयोगी साबित हो रही है।

मैं एक हजार रुपये आने से मुझे घर के जरूरी खर्चों को संभालने में सहूलियत होती है। बच्चों की फीस और सिलाई के सामान के लिए पैसे की व्यवस्था हो जाती है। अब पहले जैसी चिंता नहीं रहती।

रेखा के लिए यह सहायता केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि अपने परिवार की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने का भरोसा भी है। उनका कहना है कि महिलाओं के खाते में सीधे राशि पहुंचने से उन्हें अपनी छोटी-बड़ी



जरूरतों के लिए परिवार पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ता। इससे उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्रीमती रेखा कैवर्त कहती हैं कि महतारी वंदन योजना से उनके जैसी महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता मिल रही है। उन्होंने योजना के लिए राज्य शासन का धन्यवाद देते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग वे अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार की आवश्यकताओं में कर रही हैं।

परिवार की जिम्मेदारियों के बीच सिलाई का काम संभाल रही रेखा के लिए महतारी वंदन योजना की राशि घरेलू बजट को संतुलित करने में सहायक बनी

है। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के साथ-साथ वे अपनी टेलरिंग की छोटी-सी दुकान को भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। नियमित आर्थिक सहायता से उन्हें अपने काम और परिवार दोनों को बेहतर तरीके से संभालने का अवसर मिल रहा है।

रेखा की कहानी उन परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों को सामने लाती है, जहां सीमित आय में बच्चों की शिक्षा, घरेलू खर्च और आजीविका से जुड़े खर्च एक साथ पूरे करने होते हैं। उनके अनुभव के अनुसार, हर महीने मिलने वाली सहायता ने इन खर्चों के प्रबंधन को आसान बनाया है और परिवार की आर्थिक चिंता को कम किया है।

